मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

सांध्य दैनिक

रांची, मंगलवार, 2 जून 2026

संवत 2083, अधिक ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा 2 मूल्य-3 रुपये

वर्ष-9, अंक 258 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

4 ▶▶ एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से थमेंगे अनावश्यक विवादपानी?

वैभव को नेचुरल गेम खेलने दें, तेंदुलकर बोले सूर्यवंशी बेहद खास, टेस्ट के लिए न करें जल्दबाजी ◀◀ 6

राज्य में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज

कई जिलों में बारिश-आंधी और वज्रपात की चेतावनी

मेट्रो रेज

रांची : झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कहीं तेज गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं बारिश और ओलावृष्टि राहत पहुंचा रही है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम का यही बदला हुआ स्वरूप देखने को मिल सकता है।

राजधानी रांची समेत कई इलाकों में सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि राज्य के कई अन्य जिलों में दिनभर तेज धूप और उमस का असर बना रहा।

साइक्लोनिक सिस्टम का असरः मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने साइक्लोनिक सकुर्लेशन तथा छत्तीसगढ़ की ओर सक्रिय दूसरे साइक्लोनिक सिस्टम का प्रभाव राज्य के मौसम पर पड़ रहा है। इसी वजह से प्रदेश में कहीं तेज धूप तो कहीं बादल, बारिश और आंधी जैसी स्थिति बन रही है।

दक्षिणी और मध्य जिलों में बारिश की संभावनाः मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 जून को राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है।

विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने को कहा गया है।

4 और 5 जून को भी जारी रह सकती है बारिशः मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 और 5 जून को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राज्य के उत्तर-पूर्वी और मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

किसानों और आम लोगों के लिए सलाहः मौसम विभाग ने किसानों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और कृषि कार्यों की योजना उसी अनुसार बनाने की सलाह दी है। वहीं आम लोगों से अपील की गई है कि आंधी, बारिश और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें तथा खुले क्षेत्रों में जाने से बचें।

मौसम विभाग की चेतावनीः तेज हवा, आकाशीय बिजली और गरज के साथ बारिश के दौरान सतर्क रहें। किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थान पर शरण लें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

ईरान की अमेरिका को चेतावनी, अराघची बोले-

एक भी मोर्चे पर युद्धविराम का उल्लंघन पूरे समझौते का उल्लंघन होगा

तेहरानः ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्धविराम का किसी भी एक मोर्चे पर उल्लंघन पूरे युद्धविराम समझौते का उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अराघची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह युद्धविराम बिना किसी अस्पष्टता के सभी मोर्चों पर लागू एक व्यापक युद्धविराम है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने लिखा, इस युद्धविराम का किसी एक मोर्चे पर किया गया कोई भी उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्धविराम के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन के परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिका और इजरायल पर होगी।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने

आमजन को सरल, पारदर्शी व समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने पर दिया जोर

संवाददाता

रांचीः विभागीय समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा के बाद परिवहन विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज के बारे में जानकारी ली। बैठक में विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आमजन को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु तकनीक का व्यापक उपयोग करें। उन्होंने परिवहन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भूमि अभिलेखों के व्यापक एवं चरणबद्ध डिजिटलीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आम नागरिकों को भूमि क्रय से पूर्व संबंधित भूमि की स्थिति के संबंध में संपूर्ण एवं अद्यतन जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर सहज रूप से उपलब्ध हो सकेगी। नागरिक यह जान सकेंगे कि संबंधित भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, अधिग्रहित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से रैयतों एवं आमजनों को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी, जिससे भूमि क्रय-विक्रय से संबंधित अनिश्चितता एवं विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भूमि संबंधी सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटलीकृत कर उन्हें एकीकृत पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी स्तर पर सूचना के अभाव या विसंगति की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने अधिग्रहित भूमि के संबंधित विभागों अथवा उपयोगकर्ता एजेंसियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और भूमि से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुगम एवं प्रभावी बनेंगी।

Meri LiFE
Lifestyle for Environment
झारखण्ड वन
Citizens Foundation
WALKATHON
CYCLOTHON
For free registration
For free registration
Inspired by Nature.
For Climate.
For our Future

53rd WORLD ENVIRONMENT DAY, 2026

5 KM

ROUTE

Palash Sabhaghar | A.G. More | Spring City | Hinoo Chowk | Spring CityA.G. More | Palash Sabhaghar

3rd JUNE 2026

06:00am

10 KM

ROUTE

Palash Sabhagar | Kadru Chowk | Argora Chowk | Harmu Chowk | Sahjanand Chowk | Ratu Road Chowk
Hotlips Chowk | Ranchi College | Oxygen Park

Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand

PR No: 381257 (Forest Environment and Climate Changes) 26-27

न्यूज IN ब्रीफ

धर्म के नाम पर चंदा वसूली से वाहन चालक व राहगीर परेशान

सिल्ली : सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर दूसरों को परेशान नहीं किया जा सकता। धर्म के नाम पर सड़क रोककर, गाड़ी घेरकर चंदा के लिए भावनात्मक दबाव नही डाल सकते है। परन्तु रांची पुरुलिया मुख्य सड़क मार्ग पर बीते 10-12 दिनों से रोजाना सुबह सिल्ली में कीर्तन के नाम पर चंदा वसूली करते हुए कई युवकों को देखा जाता है। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की कतार लग जाती है सुबह का समय होने के कारण स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है। बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग कहते हैं धार्मिक आयोजन के लिए चंदा इकट्ठा करना गलत नहीं, पर इसके लिए लोकल पुलिस और डीएम से परमिशन लेना जरूरी है। बिना परमिशन सड़क पर मांगना गलत है।अगर कोई दान देना चाहता है तो मंदिर का ऑफिशियल बैंक अकाउंट या धानपेटी में सीधे दान दे सकते है। रोड पर मांगने वालों में कई फर्जी होते हैं। स्थानीय लोगों का माने तो प्रशासन की गाड़ी को आते जाते देखा जाता है पर चंदा वसूली करने वालों को कुछ नही बोला जाता है।

मरीज के परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू के लैब टेक्नीशियन पर लगाया कई गंभीर आरोप

बुंडू: अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में स्वास्थ्य व्यवस्था और कर्मियों की मनमानी का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है! बुंडू के ताऊ बिचका टोली (नियर बुण्डू बस स्टैंड के पीछे) निवासी बरुण कुमार महतो ने अस्पताल में पद स्थापित लैब टेक्नीशियन देवानंद राम के विरुद्ध कार्य में उदासीनता, लापरवाही बरतने, सरेआम गाली-- गलौज करने, शासकीय कार्य के प्रति घोर उदासीनता तथा मरीजों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता का आरोप है की उनका 11 वर्षीय पुत्र नयन कुमार का 29 मई को बलगम जांच के लिए चिकित्सक पर्ची लिखी थी। बीमार पुत्र का 1 जून तक जांच रिपोर्ट नही मिलने पर कारण पूछा तो लैब टेक्नीशियन उग्र हो गया और दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर निकाल दिया। इसे आहत पीड़ित बरुण महतो ने उक्त अस्पताल कर्मी के खिलाफ विभागीय कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

भूमि विवाद को लेकर घर पर फायरिंग करने का आरोप, तीन खोखे बरामद

चतरा : सदर थाना क्षेत्र के गोडरा गांव में भूमि विवाद को लेकर रविवार की देर रात एक परिवार के घर पर फायरिंग किये जाने का मामला सामने आया है।घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से तीन खोखा बरामद कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, गोडरा गांव निवासी अरुण कुमार सिंह के घर पर रविवार रात करीब 12 बजे कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचे और घर के बाहर फायरिंग करने लगे।अचानक गोलियों की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य सहम गये और भय के कारण कुछ देर तक घर से बाहर नहीं निकल सके।बाद में आसपास के ग्रामीणों के जुटने पर परिजन घर से बाहर निकले और डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी।सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची।पुलिस ने घर के बाहर से तीन खोखा बरामद किया है। इस संबंध में भुक्तभोगी अरुण कुमार सिंह ने सदर थाना में आवेदन देकर 12 नामजद तथा कई अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।आवेदन में राजेंद्र यादव, दिनेश्वर यादव, प्रेम यादव, पप्पू कुमार यादव, मुनेश्वर यादव, खिरोधर यादव, मन्नु यादव, कुंजल यादव, विनोद यादव, लखन यादव, छोटू यादव, एकबाल मियां, सुबोध ठाकुर समेत कई अज्ञात का आरोपी बनाया है। भुक्तभोगी का आरोप है कि सभी आरोपी उनकी जमीन हड़पने की नीयत से रात में हथियारों के साथ पहुंचे और घर के बाहर फायरिंग करते हुए गाली-गलौज की।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है तथा इस मामले में अंचल और थाना स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से आरोपियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

चंद्रपुरा पावर प्लांट में विस्थापितों और स्थानीय का जोरदार प्रदर्शन

बोकारो : जिले में 1 जून सोमवार की शाम चंद्रपुरा पावर प्लांट के मुख्य द्वार में दस सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित और स्थानीय संघर्ष समिति ने विराट प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में आसपास के गांवों के महिला-पुरुषों सहित युवा वर्ग ने पारंपरिक हथियार के साथ भाग लिया।

डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ की नारेबाजीः जुलूस में प्लांट गेट पहुंचे लोगों ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

15 दिन में मांगें पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन : प्रदर्शन को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक लखी हेम्ब्रम ने कहा कि डीवीसी ने हमारे सीधे सादे पूर्वजों से जमीन ले ली मगर ना तो सुविधायें दी और ना नौकरी। इस बार यहां 1600 मेगावाट का नया प्लांट लगना है इसलिए इसमें विस्थपितों और स्थानीय युवकों को नौकरी देना, सीएसआर में विस्थापित के एक सदस्य को रखने, विस्थापितों को संवेदक बनाने और विस्थापित गांवों में विकास करने की हमारी मांग को पूरा करना होगा नहीं तो यहां पर 15 दिनों के बाद जोरदार आंदोलन किया जाएगा।

डिनोबिली स्कूल के लिए जमीन देने का किया विरोध : उन्होंने डीवीसी प्रबंधन द्वारा डिनोबिली स्कूल के लिए आवासीय कॉलोनी में जमीन देकर स्कूल बनाने के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि जिस स्कूल में गरीबों की पढ़ाई आरटीई के तहत निःशुल्क नहीं होती हो और डीवीसी के बच्चों को भी फीस में छूट नहीं मिलती हो वैसे स्कूल की यहां जरूरत नहीं है।

नशामुक्त बनाने के लिए महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली

खरसावां: खुंटपानी प्रखंड के पुरुनियां गांव में महिला समितियों ने गांव को नशामुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसको लेकर गांव में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नशे के बढ़ते प्रचलन और उसके दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा हुई। गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए रैली निकाली गई। गांव में शराब की बिक्री नहीं करने देने की बात कही गई।

नशामुक्त गांव बनाने का सामूहिक संकल्प : बैठक में बताया गया कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी बीड़ी, सिगरेट, गांजा और खैनी जैसी नशीली वस्तुओं के सेवन के आदी होते जा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है।

डीएमओ पर 17.29 करोड़ की रॉयल्टी गड़बड़ी और घूसखोरी के गंभीर आरोप

पत्थर कारोबारी ने श्रीनिवास ने प्रेस वार्ता आयोजित कर खोला मोर्चा

नियमों को ताक पर रख काम करने का आरोप

ईडी,एसीबी व सीबीआई तक की गई है शिकायत

संवाददाता

चतरा : जिले के हंटरगंज प्रखंड निवासी एवं चर्चित पत्थर कारोबारी श्रीनिवास सिंह ने जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ब्लैकमेलिंग तथा सरकारी राजस्व में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। समाहरणालय के समीप एक होटल में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्रीनिवास ने दावा किया उनके पास व्हाट्सएप चैट, विभागीय दस्तावेज और अन्य कई साक्ष्य मौजूद हैं, जो जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो को भ्रष्ट व घूसखोर अधिकारी साबित करने के लिये पर्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन परियोजना में कार्यरत एजेंसियों के माध्यम से करीब 28 महीनों तक फर्जी माइनिंग रॉयल्टी चालान जारी किए गए, जिसके कारण सरकार को लगभग 17 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में जिला खनन कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है और इसकी निष्पक्ष जांच होने पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। श्रीनिवास ने बताया कि मामले की शिकायत उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) समेत अन्य जांच एजेंसियों से भी लिखित तौर पर की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से डीएमओ के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर पुरे मामले कि निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पूरे मामले की जांच कराई जाती है तो यह झारखंड के सबसे बड़े खनन घोटालों में से एक साबित हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि जांच आगे बढ़ने पर घोटाले की राशि 17 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। श्रीनिवास ने यह भी आशंका जताया है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद वास्तविक दोषियों को बचाने और मामले की लीपापोती करने के लिए विभाग के निचले स्तर के किसी कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वह इसका भी विरोध करेंगे और मामले को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर चतरा में चल रहे अवैध खनन, बालू, पत्थर कारोबार पर लगाम नहीं लगाया गया और दोषी डीएमओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो बाध्य होकर वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं श्रीनिवास नें खनन कार्यालय व डीएमओ के संरक्षण में नियम विरुद्ध निर्गत माइंस व अन्य क्रशरों के संचालन पर भी सवाल खड़े किये हैं। कहा है कि डीएमओ और खनन कार्यालय को बगैर सीटीओ और अन्य महत्वपूर्व दस्तावेज संचालित क्रशर और माइंस नहीं दिखते। जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और घूसखोरी का जीता जागता सबूत है। वहीं दूसरी ओर जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला 17।29 करोड़ रुपये नहीं बल्कि करीब 26 करोड़ रुपये की रॉयल्टी गड़बड़ी से जुड़ा है, जिसका खुलासा स्वयं खनन विभाग द्वारा किया गया है। डीएमओ के अनुसार मामले की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उच्चाधिकारियों के निदेर्शानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।जांच में परियोजना से जुड़ी एजेंसी इरकॉन तथा उसकी सहयोगी कंपनी राजा कंस्ट्रक्शन द्वारा सरकारी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के दुरुपयोग के संकेत मिले हैं। इसी आधार पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। बहरहाल दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच मामला जिले के साथ-साथ राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच, संभावित एफआईआर और उच्च स्तरीय कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

सराक समाज खूंटी जिला की मासिक बैठक में संगठन का गठन, नए पदाधिकारियों का चयन

संवाददाता

खूंटीः राजस्थान भवन, खूंटी में सराक समाज, खूंटी जिला की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में समाज के सदस्य एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रो एनके मांझी ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य सराक समाज को अधिक संगठित, सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए जिला स्तरीय संगठन का गठन तथा नए पदाधिकारियों का चयन करना था। सर्वसम्मति से संगठन के विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में संजय कुमार मांझी (हेसल) को अध्यक्ष, पुरेंद्र मांझी (सुंदारी) को उपाध्यक्ष, दयानंद मांझी (माहिल) को सचिव, राकेश मांझी (हाँसा) को उप सचिव, प्रतिम मांझी (माहिल) को कोषाध्यक्ष, सुमन कुमार मांझी (माहिल) को उप कोषाध्यक्ष तथा प्रसून कुमार मांझी (घाघरा) को संयोजक सह प्रवक्ता चुना गया।

इसके अलावा संगठन मंत्री के रूप में गणेश मांझी (खूंटी), राजकुमार मांझी (गजगांव), सुबोध मांझी (मेराल), अनित मांझी (घाघरा), अनुप मांझी (बिरामकेल), शिवकुमार मांझी (डोरमा), जगदीश मांझी (कसमार), सुभाष मांझी (कसमार) एवं गिरिधारी मांझी (बरटोली) का चयन किया गया। बैठक में उपस्थित समाज के सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में सराक समाज और अधिक संगठित होगा तथा शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण एवं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी कार्य किए जाएंगे।

अंत में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गईं और समाज हित में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।

83.79 किलो अफीम डोडा जब्त

चतराः जिले में एसपी अनिमेष नैथानी के नेतृत्व में मादक पदार्थों की बरामदगी लगातार हो रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 83.79 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया है। मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नेटवर्क से जुड़े एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि थाना क्षेत्र के चरका खुर्द गांव में की गई छापेमारी के दौरान चतरा पुलिस द्वारा एक घर से छह बोरियों में रखा अफीम डोडा जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार बरामद खेप को बिहार ले जाकर बेचने की तैयारी थी। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत 12 लाख 56 हजार 850 रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि तस्करी में संलिप्त एक तस्कर सुनील कुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि जांच में एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसपी श्री नैथानी ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

ग्रामीणों ने कंपनी पर मनमानी का लगाया आरोप, आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

चतराः जिले के टंडवा प्रखंड की कबरा पंचायत में प्रस्तावित कोल परिवहन मार्ग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और संबंधित कंपनी के बीच विवाद गहरा गया है। पंचायत वासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा बिना पर्याप्त प्रशासनिक स्वीकृति और वैधानिक अधिसूचना के निजी कोयला परिवहन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रस्तावित सड़क घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है, जिससे स्थानीय निवासियों, स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा आम जनजीवन की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में पूर्व में भी विभिन्न तिथियों पर प्रशासन को आपत्तियां दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण से कृषि भूमि, पर्यावरण और स्थानीय जलस्त्रोतों पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। पंचायत वासियों ने विशेष रूप से वृंदा क्षेत्र स्थित बड़की नदी के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रस्तावित मार्ग नदी के समीप से गुजर रहा है। इससे कोयला परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल और मलबे के कारण नदी और आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि भारी वाहनों के संचालन से क्षेत्र की कृषि गतिविधियां और पशुधन भी प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बड़की नदी पर बने पुल के समीप स्थित तीव्र मोड़ को दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील बताते हुए कहा कि कोयला वाहनों की आवाजाही बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने, संबंधित कंपनी की भूमिका की जांच कराने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।।पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आक्रोशित ग्रामीण आज से अनिश्चितकालीन चक्का जाम एवं जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं।

सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक

विकास योजनाओं एवं पूर्व निर्देशों के अनुपालन की हुई समीक्षा

लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश

संवाददाता

चतराः समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में चतरा सांसद सह अध्यक्ष जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 24 दिसंबर 2025 को आयोजित दिशा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विभागवार समीक्षा की गई तथा विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक के प्रारंभ में सांसद, क्षेत्रीय विधायकों, जिला परिषद अध्यक्षा एवं नगर परिषद अध्यक्ष का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। इसके उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण कार्य विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, विद्युत विभाग, भूमि संरक्षण, शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग, जिला परिषद, सहकारिता विभाग, एनटीपीसी, सीसीएल एवं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से संबंधित मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

बैठक में सड़क, पुल-पुलिया एवं अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इटखोरी क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि शेष प्रक्रियाएं पूर्ण करते हुए कार्य को शीघ्र गति प्रदान की जाएगी। इस पर सांसद ने आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निमार्णाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया।समीक्षा के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि कुछ योजनाएं वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के कारण लंबित हैं। इस पर संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने तथा योजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, जलमीनार, पाइपलाइन विस्तार तथा जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। विद्युत विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने, लंबित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा जनसुविधा से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर बल दिया गया।बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े विभिन्न मामलों की भी समीक्षा की गई। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू संचालन व्यवस्था तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों को रखने का अवसर दिया गया। इस क्रम में रेड क्रॉस भवन निर्माण, स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता, एंबुलेंस व्यवस्था, पेयजलापूर्ति, सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण, ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास सहित विभिन्न जनहित के मुद्दे उठाए गए। संबंधित विभागों को प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सांसद ने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर कार्य करें तथा जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।बैठक में उपायुक्त रवि आनंद, विधायक चतरा जनार्दन पासवान, विधायक सिमरिया उज्ज्वल कुमार दास, विधायक बड़कागांव रौशन लाल चौधरी, सांसद हजारीबाग प्रतिनिधि रविन्द्र सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी (उत्तरी) राहुल मीणा, वन प्रमंडल पदाधिकारी (दक्षिणी) मुकेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्षा ममता कुमारी, नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान, उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सन्नी वर्धन, जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शकील अहमद, सभी प्रखंड प्रमुख, विभागीय पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

रात के अंधेरे में एसडीएम का विशेष अभियान, नशा करने वालों पर कसा शिकंजा

सड़क से चौक-चौराहों तक छापेमारी

मेट्रो रेज

रांची : अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) के नेतृत्व में देर रात विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों पर नशा करने वालों और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सघन जांच एवं छापेमारी की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से नशा करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया।

अभियान के दौरान शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, सुनसान क्षेत्रों तथा नशे के संभावित अड्डों पर व्यापक जांच की गई। प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की तथा आवश्यक जांच-पड़ताल की।

एसडीएम ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी, कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों और सामाजिक माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ प्रशासन का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और सुरक्षित सामाजिक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि यदि कहीं नशाखोरी या अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अंजुमन इस्लामिया चुनाव मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल को नोटिस जारी

24 जून को ट्रिब्यूनल में पेश होने का निर्देश, अनुपस्थित रहने पर एकतरफा सुनवाई होगी

गुलाम शाहिद

रांचीः झारखंड वक्फ ट्रिब्यूनल ने अंजुमन इस्लामिया की प्रबंध समिति (मजलिस-ए-मुन्तजिमा-2025) के चुनाव से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला मोहम्मद शमीम अख्तर द्वारा दायर याचिका पर दर्ज किया गया है, जिसमें झारखंड सरकार, झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड, रांची के उपायुक्त, चुनाव संयोजक काजी मोहम्मद अनवर कश्मी, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) तथा अंजुमन इस्लामिया को पक्षकार बनाया गया है।

ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मुख्तार अहमद को 24 जून 2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से अथवा विधिवत अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर याचिका पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित तिथि पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया या उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई, तो ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई एकतरफा (एक्स-पार्टी) करते हुए निर्णय ले सकता है।

यह नोटिस 22 मई 2026 को झारखंड वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया है। मामले को अंजुमन इस्लामिया की प्रबंध समिति के चुनाव संबंधी विवाद से जुड़ा माना जा रहा है, जिसकी सुनवाई अब 24 जून को होगी।

जेपीएससी ने सिविल जज पीटी रिजल्ट के 22 महीने बाद जारी किया मॉडल आंसर-की

संवाददाता

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सिविल जज (जूनियर डिविजन) प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) रिजल्ट के 22 महीने बाद फाइनल आंसर-की जारी कर दिया है। इस स्थिति में अब आयोग को एक बार फिर पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा।

2024 में हुई थी परीक्षा : कुल 138 पद के लिए आयोग ने 10 मार्च 2024 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया था। तीन बार मॉडल उत्तर जारी करने के बाद आयोग ने दो जुलाई 2024 को रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया। इसमें 1797 अभ्यर्थी सफल हुए। मॉडल उत्तर पत्र में त्रुटि, आरक्षण और दिव्यांग कोटा को लेकर विवाद को लेकर मामला हाइकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पूरे मामले में हाइकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन नहीं होने और संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दायर कर दी। जिस पर कोर्ट ने आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई। अंततः मुख्य परीक्षा लेने से पहले ही इस पर ब्रेक लग गया।

चार महीने बाद आंसर-की जारी : नौ फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। निर्देश के लगभग चार महीने बाद सोमवार जारी फाइनल आंसर-की में कुल 100 प्रश्न में पांच प्रश्न के पूर्व के उत्तर में सुधार कर किया गया है। जबकि दो प्रश्न ड्रॉप कर दिए गए हैं। यानी दो प्रश्न को प्रश्न पत्र से ही बाहर कर दिया गया है। वहीं तीन प्रश्न के दिए गए सभी विकल्प गलत पाए गए। इस स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को एक-एक यानी कुल तीन अंक मिलेंगे। अब फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद आयोग जल्द ही संशोधित कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी करते हुए मुख्य परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा।

2023 से चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया : आयोग में सिविल जज (जूनियर डिविजन) नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त 2023 से चल रही है। कुल 138 पदों में अनारक्षित के 60 पद, एसटी के 28 पद, एससी के 12 पद, बीसी वन के 10 पद, बीसी टू के 15 पद और इडब्ल्यूएस के 13 पद शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

छात्रों को मिलेगी ई-साइकिल, कल्याण योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश

मेट्रो रेज

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया और अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि सरकार अब विद्यार्थियों को पारंपरिक साइकिल के स्थान पर ई-साइकिल (इलेक्ट्रिक साइकिल) उपलब्ध कराएगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक, सुविधाजनक एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी शिक्षा तक पहुंच और अधिक सुगम हो सके।

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र लाभुकों तक पहुंचे। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।

समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित निगरानी करने और जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

होटवार जेल में यौन शोषण

बेल पर रिहा महिला कैदी ने कहा-मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ

रांचीः होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद एक महिला कैदी के साथ दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने की चचाओं के बीच मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद महिला ने स्वयं सामने आकर इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है।

ब्राउन शुगर पैडलिंग के मामले में गिरफ्तार महिला होटवार जेल में बंद थी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म होने तथा गर्भवती होने की खबरें सामने आई थीं। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस वार्ता कर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने भी संज्ञान लिया था। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद महिला ने कहा कि उसके साथ जेल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलत घटना नहीं हुई। उसने स्पष्ट किया कि न तो उसने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और न ही जेल परिसर में किसी तरह की अनैतिक गतिविधि हुई है। महिला ने यह भी कहा कि जेल के अंदर इस प्रकार की घटना होना संभव नहीं है। महिला ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस तरह की खबरें और आरोप बाहर कैसे पहुंचे, इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। वहीं उसकी मां ने भी बेटी के साथ किसी प्रकार की गलत घटना होने से इनकार किया है।

पीड़िता और उसके परिवार के बयान के बाद होटवार जेल में दुष्कर्म और गर्भवती होने के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर इस तरह की खबरें किस आधार पर सामने आईं और मामले की वास्तविकता क्या है।

अंजुमन अस्पताल में ओपीडी शुल्क वृद्धि का विरोध पंचायत युवा संघ ने बताया जनविरोधी फैसला

संवाददाता

रांचीः अंजुमन अस्पताल में ओपीडी शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 100 और 200 रुपये किए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। जमीअतुल कुरैश चीख पंचायत युवा संघ के सचिव मोहम्मद अकबर कुरैशी ने इस निर्णय को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह फैसला बिना व्यापक राय-मशविरा के लिया गया है, जिससे आम लोगों में नाराजगी है।मोहम्मद अकबर कुरैशी ने कहा कि वर्तमान में अंजुमन की मौजूदा कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे समय में अस्पताल के ओपीडी शुल्क में अचानक बढ़ोतरी का फैसला लेना उचित नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव संपन्न होने और नई कमेटी के गठन के बाद इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने चाहिए थे।उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अस्पताल प्रबंधन को किसी प्रकार की आर्थिक या प्रशासनिक परेशानी थी, तो अंजुमन के जिम्मेदार लोगों, सामाजिक प्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों को बुलाकर रायशुमारी की जानी चाहिए थी। सामूहिक चर्चा और सहमति के बाद लिया गया निर्णय लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य होता।

युवा संघ सचिव ने कहा कि बिना परामर्श के ओपीडी शुल्क बढ़ाने का निर्णय आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने तथा सभी पक्षों को विश्वास में लेकर आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन को पारदर्शी तरीके से निर्णय लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

एडीजी ने बेहतर कार्य के लिए पिठौरिया थानेदार को किया सम्मानित

मेट्रो रेज

रांची : एडीजी मनोज कौशिक ने पिठौरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सतीश कुमार पांडे को बेहतर कार्य और प्रदर्शन के लिए एडीजी ने सम्मानित किया। बता दें कि सतीश कुमार पांडे 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कई केसों का सफलता पूर्वक अनुसंधान किया है।

प्रशस्ति पत्र अक्सर अपराधियों की धरपकड़ या कानून व्यवस्था बनाएं रखने में दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों के साहस और कड़ी मेहनत की सराहना उनका मनोबल बढ़ाना होता है। जिससे वे भविष्य में भी पूरी ऊर्जा से काम करें।

अन्य कर्मियों को मिलें प्रेरणाः इसका उद्देश्य पारदर्शिता और अच्छे काम को सार्वजनिक रूप से मान्यता देना है। जिससे विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिले। इसलिए पुलिस के आला अधिकारी अक्सर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दारोगा के आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। जो भविष्य में उनके प्रमोशन में बहुत मददगार साबित होता है।

वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के 14वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

मेट्रो रेज संवाददाता

धुर्वाः युवा ब्रह्मषि समाज, धुर्वा ट्रस्ट के तत्वावधान में वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के 14वें शहादत दिवस पर स्वामी सहजानंद परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके वक्ताओं ने उनके सामाजिक योगदान, आदर्शों और जीवन मूल्यों को याद करते हुए समाज को संदेश दिया। कहा कि कठिन समय में अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से ग्रामीण समाज की सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया को याद करना हमारा कर्तव्य है। जिन्होंने अपने-अपने तरीके से उस दौर में जब हमारा समाज नक्सली हिंसा, भय ,असुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया और ग्रामीण जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। श्रद्धांजलि सभा में गणमान्य अभिभावक एवं ट्रस्ट के संरक्षक अनिल शर्मा, प्रेम सागर सिंह, अध्यक्ष पंकज कुमार,सचिव राम सिंह, कोषाध्यक्ष रामराज, उपाध्यक्ष राम बोल कुंवर,महेश कुमार,कमलेश शर्मा,मुरारी सिंह, संजीत कुमार,धीरेन्द्र सिंह बमबम,हरिशंकर तिवारी,वीरेंद्र तिवारी ने श्रद्धासुमन अर्पित किया।

ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर शुरू

मेट्रो रेज

रांचीः रांची जिला वुशु एसोसिएशन एवं झारखंड वुशु एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित वुशु हॉल में आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वुशु प्रशिक्षण शिविर का आज विधिवत शुभारंभ किया गया।शिविर का उद्घाटन झारखंड सेपक टकरा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री उदय साहु ने किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, अनुशासन एवं समर्पण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में झारखंड वुशु एसोसिएशन के सचिव श्री शैलेन्द्र दुबे, वुशु कोच दीपक गोप सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे।

शिविर में रांची जिले के खिलाड़ियों के साथ-साथ राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को वुशु खेल की विभिन्न तकनीकों, कौशल एवं प्रतियोगितात्मक तैयारियों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

यह ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 10 जून 2026 तक संचालित होगा। आयोजकों ने खिलाड़ियों से शिविर का अधिकतम लाभ उठाकर अपने खेल कौशल को और बेहतर बनाने का आह्वान किया है।

रॉंची समाहरणालय,रॉंची
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
जिला बाल संरक्षण इकाई

गुमशुदा बालक की सूचना
(बाल कल्याण समिति, रांची के आदेशानुसार)

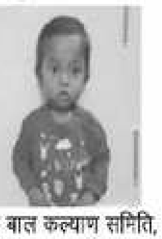

. नाम– रवि (काल्पनिक नाम)
. लिंग– बालक
. पिता का नाम– अज्ञात
. माता का नाम– अज्ञात
. पता– अज्ञात
. उम्र – 01 वर्ष 01 माह (लगभग)
. रंग – सांवला

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाल कल्याण समिति, रॉंची के आदेशानुसार एक (01) बालक रवि (काल्पनिक नाम) उम्र–01 वर्ष 01 माह (लगभग) को करूणा एन०एम०ओ०, रॉंची में आवासित किया गया है। जिसके जैविक एवं विधिक संरक्षक का पता लगाने हेतु राज्य स्तरीय एवं स्थानीय अखबार में विज्ञापन प्रकाशित की गयी है। उक्त बालक के जैविक एवं विधिक संरक्षक का विज्ञापन प्रकाशन के 60 दिनों (दो माह) तक कोई दावा प्रस्तुत नहीं होने पर दत्तक ग्रहण मार्गदर्शिका 2017 के नियम, 6 के उपनियम, 13 के अन्तर्गत बालक को दत्तक ग्रहण हेतु बाल कल्याण समिति, रॉंची द्वारा कानूनी रूप से मुक्त किया जा सकेगा।

दावा प्रस्तुत करने का पता एवं संपर्क नम्बर–
1. बाल कल्याण समिति, रॉंची
रॉंची समाहरणालय, रॉंची, भवन–ब्लॉक बी,
कमरा संख्या–110
2. जिला बाल संरक्षण इकाई, रॉंची।
रॉंची समाहरणालय, रॉंची, भवन–ब्लॉक बी,
कमरा संख्या–111
सम्पर्क सूत्र–06513505516

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी,
रॉंची।

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, रॉंची।

PR 381195 (Women, Child Development & Social Security) 26-27 (D)

सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

हिंसा छोडकर लोकतांत्रिक मूल्यों का करें पालन

पश्चिम बंगाल में पहले अभिषेक बनर्जी और एक दिन बाद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। राज्य में चुनाव हो गए, सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। पहले भाजपा विपक्ष में थी तो उसके नेता निशाना बनते थे, आज तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में है तो उसके नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई घटना नहीं है। यह राज्य दशकों से खून-खराबे और हत्याओं का गवाह रहा है। भारत में राजनीतिक हत्याओं की दर सबसे अधिक यहीं रही है। 1946 के दंगों और नोआखली हिंसा से लेकर 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन तक बंगाल में हिंसा की जड़ें गहरी हैं। 1970 का सांईबाड़ी हत्याकांड जैसे काले अध्याय आज भी याद किए जाते हैं। वाम मोर्चा शासनकाल में भी हिंसा की घटनाएं देखने में आती रहीं। 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो उम्मीद जगी थी कि हिंसा थम जाएगी, लेकिन स्थिति ज्यादा नहीं बदली। तृणमूल शासन में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, 2014 से लेकर अब तक बंगाल में भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। अब भाजपा सरकार में तृणमूल नेताओं पर हमले हो रहे हैं। स्पष्ट है कि बंगाल में हिंसा मुख्य रूप से विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है। सत्ता जिसके पास होती है, विपक्ष उसी का शिकार होता रहा है। देश के बाकी राज्यों में चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, एक पार्टी जीतती है तो दूसरी हारती है, लेकिन कहीं भी बंगाल जैसी निरंतर राजनीतिक हिंसा नहीं दिखती। बंगाल में दुर्भाग्य से हिंसा को राजनीतिक हथियार बना लिया गया है। हालांकि यहां यह भी मानना पड़ेगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद 2021 जैसी भारी हिंसा की खबरें नहीं आईं। यह एक सकारात्मक बदलाव है। फिर भी हाल के दिनों में तृणमूल नेताओं पर हुए हमले दिखाते हैं कि समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। बंगाल की राजनीति में हिंसा को अब सामान्य नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में मतभेदों को हिंसा से नहीं, संवाद और कानून के रास्ते से सुलझाना चाहिए। नई सरकार को कानून-व्यवस्था को मजबूत करना होगा और सभी दलों को हिंसा छोड़ कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। जब तक बंगाल में यह हिंसा का चक्र जारी रहेगा, लोकतंत्र की सच्ची जीत नहीं हो सकती। सत्ता बदलती रहेगी, लेकिन अगर खून बहता रहा तो विकास और शांति सिर्फ सपना बनी रहेगी। राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह राजनीतिक हिंसा को पूरी तरह रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। भाजपा को अब यह करके दिखाना होगा, क्योंकि वह खुद विपक्ष में रहकर लंबे समय तक राजनीतिक हमलों के खिलाफ लड़ती आई है। साथ ही अन्य सभी राजनीतिक दलों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संयम बरतना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करना चाहिए।

एआइ का बुलबुला और कंपनियों की समझदारी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) मानव इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति जरूर है लेकिन, इससे अतिशयोक्तिपूर्ण अपेक्षाओं की हवा अब निकलने लगी है। यह समझ लेना कि एआइ मानव संसाधन का स्थान ले लेगा वास्तविकता को बढ़ा-चढ़ाकर आंकने जैसा है। एआइ, दरअसल एक मशीन ही है और इससे काम लेने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। प्रतिष्ठित ग्लोबल रिसर्च कंपनी 'गार्टनर' की हालिया रिपोर्ट एआइ की उपयोगिता और उस पर हो रहे अंधाधुंध खर्च को लेकर तीखे सवाल खड़े कर रही है। यह चर्चा अब तेज हो रही है कि क्या एआइ का 'बुलबुला' (हाइप) फूटने की कगार पर है? वैश्विक स्तर पर एआइ के विकास को समझने के लिए गार्टनर की 'हाइप साइकल फॉर जेनरेटिव एआइ' सटीक पैमाना माना जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी नई तकनीक पांच चरणों से गुजरती है। एआइ अब 'अतिशयोक्तिपूर्ण उम्मीदों के शिखर' को पार कर 'मोहभंग के दौर' में प्रवेश कर चुका है।

कंपनियों ने एआइ से जो तात्कालिक वित्तीय लाभ और उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद की थी, वह धरातल पर वैसी साबित नहीं हो रही है। एआइ प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की अत्यधिक लागत, डेटा सुरक्षा की चिंताएं और एआइ की गलत या भ्रामक जानकारियां इसके मुख्य कारण हैं। 'गार्टनर' की रिपोर्ट में चेतावनी है कि कम से कम 30 फीसदी जेनरेटिव एआइ प्रोजेक्ट भारी लागत और अपना स्पष्ट वैल्यू साबित न कर पाने के कारण शुरूआती दौर के बाद बंद हो सकते हैं। इस तकनीकी अति-उत्साह का सबसे दुखद प्रभाव मानव संसाधन पर पड़ा है। वैश्विक टेक दिग्गजों ने एआइ को अपनाकर लागत कम करने के नाम पर लाखों कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनियों को लगा कि एआइ कोडिंग, कंटेंट निर्माण और ग्राहक सेवा जैसे काम बिना किसी इंसानी मदद के संभाल लेगा। लेकिन एआइ अभी तक जटिल निर्णय लेने, रचनात्मकता दिखाने और मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह समझने में अक्षम साबित हुआ है। उल्टे छंटनी की वजह से कंपनियों ने अपने सबसे मूल्यवान 'संस्थागत ज्ञान' को खो दिया है। यह स्थिति कंपनियों के लिए 'पछतावे का सबब' बन सकती है।

गनीमत है कि भारत में एआइ अपनाने के मामले में अपेक्षाकृत सावधानी बरती जा रही है। ज्यादातर कंपनियों ने अंधाधुंध छंटनी करने की बजाय अपने कर्मचारियों को एआइ कौशल सीखने के लिए प्रेरित किया है। 'एआइ घोड़े' (मशीन) को अपनाने की बेहतर रणनीति यही है कि धीरे-धीरे उसे परिपक्व होने दिया जाए और साथ ही साथ मानव संसाधन को भी उसकी सवारी करने के लिए तैयार किया जाए। एआइ के कारण 'जॉब स्ट्रक्चर' में व्यापक बदलाव होना अवश्यम्भावी है, पर इसे सहजता से मानव जीवन का हिस्सा बनने दिया जाना समय की पुकार है।

एसआइआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से थमेंगे अनावश्यक विवादपानी?

> अब यह केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि नागरिकता की परख के मानदंडों को स्पष्ट और न्यायसंगत बनाया जाए। लेकिन वैध नागरिकों के मताधिकार को मजबूत करने वाली पहल अर्थात एसआइआर, पर केवल राजनीतिक कारणों से प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। बेहतर यही होगा कि विपक्षी दल इस फैसले को स्वीकार करें और चुनावों के दौरान अनावश्यक विवाद खड़े करने से बचें।

प्रियरंजन भारती

एसआइआर कोई चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजे पहले ही इस बात को स्थापित कर चुके हैं। इसे जबरिया मुद्दा बनाने की कोशिशें की गईं, मगर मतदाताओं ने इसे वाजिब माना ही नहीं। यदि ऐसा होता, तो इसका असर चुनाव परिणामों पर दिखाई देता। बल्कि इसके विपरीत प्रभाव यह पड़ा कि मतदाताओं ने निष्पक्ष और साफ-सुथरे मतदान के प्रयासों को प्रभावित करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम इस बात के प्रत्यक्ष और सशक्त उदाहरण हैं। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर व्यापक विरोध जताया और अदालतों में स्वयं पक्ष रखने तक पहुंच गईं। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनके समर्थकों के वोट साजिश के तहत हटाने का काम कर रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष पर्यवेक्षकों की निगरानी में एसआइआर की प्रक्रिया पूरी की गई।

इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने अनेक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन किए और इस अभियान में जुटे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ जोर-जबरदस्ती की। इसके बावजूद चुनाव परिणाम यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जनता ने टीएमसी और ममता बनर्जी के इन प्रयासों को न केवल खारिज किया, बल्कि एसआइआर को निष्पक्ष चुनाव के एक आवश्यक और उचित प्रयोग के रूप में स्वीकार किया। यदि यह कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में पहले से भय और दबाव के माहौल में रहने वाले मतदाताओं को एसआइआर ने स्वतंत्र और निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जितने उपाय किए गए, उनमें एसआइआर का योगदान भी महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है।

झूठ और दुष्प्रचार अधिक समय तक टिक नहीं सकतेः अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एसआइआर न तो अवैध है और न ही इसकी उपयोगिता पर अनावश्यक प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है। इस निर्णय ने जनता के उस विश्वास को और अधिक मजबूत आधार प्रदान किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एसआइआर जैसी प्रक्रिया आवश्यक है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन लोगों के लिए बड़ा झटका है, जो लगातार यह प्रचार कर रहे थे कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के कहने पर एसआइआर के बहाने चुनावी मनमानी करने में जुटा है। इस आदेश ने यह भी सिद्ध कर दिया कि झूठ और दुष्प्रचार अधिक समय तक टिक नहीं सकते। किसी वैध और आवश्यक प्रक्रिया को केवल प्रचार के आधार पर रोका नहीं जा सकता।

लोकतंत्र में जनविश्वास सर्वोपरिः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनविश्वास सर्वोपरि होता है। इस अभियान की सार्थकता भी जनता के इसी भरोसे में निहित दिखाई देती है। यही कारण है कि मतदाताओं ने राजनीतिक दलों के एसआइआर-विरोधी प्रचार को सच के रूप में स्वीकार नहीं किया। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एसआइआर का विरोध कुंठा से अधिक कुछ नहीं है। निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त यह है कि केवल वैध मतदाता ही भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। किसी व्यक्तिके वैध मतदाता होने या न होने का निर्धारण करने के लिए आवश्यक जांच-पड़ताल करना चुनाव आयोग का अधिकार भी है और दायित्व भी।

नहीं प्रस्तुत कर सके ठोस उदाहरण

यह आश्चर्यजनक है कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग के इसी अधिकार को चुनौती देते हुए यह आरोप लगा रहे थे कि आयोग इस बहाने उनके समर्थकों के वोट काटने की साजिश कर रहा है। ऐसे आरोपों के माध्यम से यह वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि यह अभियान केंद्र सरकार की कथित चुनावी साजिश का हिस्सा है। हालांकि, इन लोगों ने कभी यह बताने का प्रयास नहीं किया कि जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं, वे वास्तव में उनके समर्थक ही हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार में भी इसी प्रकार की आशंकाएं और आरोप लगाए गए थे। बिहार में एसआइआर के दौरान जब लगभग 65 लाख अप्रासंगिक या अनावश्यक नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तब भी शोर मचाया गया कि वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे आरोप लगाने वाले कुछ दर्जन ठोस उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं कर सके।

केंद्र सरकार एनआरसी जैसे विषयों पर स्पष्ट नीति विकसित करेः बिहार विधानसभा चुनाव में भी एसआइआर कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दल जनता की मनोदशा को समझने में असफल रहे। परिणाम ऐसे आए कि हवा बनाने वाले स्वयं राजनीतिक हवा में उड़ गए। विडंबना यह है कि बिहार चुनाव परिणामों से भी इनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया और असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में भी एसआइआर के विरोध का वही क्रम जारी रहा। इन राजनीतिक दलों को इस बात पर भी आपत्ति थी कि एसआइआर के बहाने लोगों की नागरिकता की जांच की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग नागरिकता से संबंधित आवश्यक जांच कर सकता है। आखिर इसी आधार पर यह तय किया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति भारत का वैध नागरिक है या नहीं। इसके साथ ही यह तथ्य भी सामने आया है कि नागरिकता की जांच के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग की जांच को नागरिकता संबंधी अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे विषयों पर स्पष्ट नीति और व्यवस्था विकसित करे।

फैसले को स्वीकार करें विपक्षी दल : अब यह केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि नागरिकता की परख के मानदंडों को स्पष्ट और न्यायसंगत बनाया जाए। लेकिन वैध नागरिकों के मताधिकार को मजबूत करने वाली पहल अर्थात एसआइआर, पर केवल राजनीतिक कारणों से प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। बेहतर यही होगा कि विपक्षी दल इस फैसले को स्वीकार करें और चुनावों के दौरान अनावश्यक विवाद खड़े करने से बचें। जनता अब एसआइआर और वोट चोरी जैसे आरोपों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। यदि इन आरोपों में वास्तविकता होती, तो चुनाव परिणामों पर उसका प्रभाव भी दिखाई देता।

मतदाता को भ्रमित नहीं किया जा सकताः हार के बाद लगातार एक ही प्रकार के बहाने दोहराना जनता को स्वीकार्य नहीं है। जीत के समय वोट चोरी और एसआइआर की चर्चा न करने वाले दलों को यह समझना चाहिए कि समझदार मतदाता को लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। जनता अब यह भली-भांति समझ चुकी है कि कई बार अपनी राजनीतिक कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा, भारत की स्थिति व पीएम की यात्राएं

> पिछले लगभग 3 माह से चल रहे युद्ध के चलते देश के समक्ष एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, जो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, बाधित आपूर्ति आदि के कारण देश में महंगाई बढ़ने लगी है। इसलिए दीर्घकाल के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वे अल्पकाल के लिए शायद काफी नहीं हैं। देश में आने वाले कुछ समय तक पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को भी दूर करना जरूरी है।

डा. अश्विनी महाजन

एक ओर अमेरिका और इजरायल तथा दूसरी ओर ईरान के बीच युद्ध को लगभग तीन महीने होने जा रहे हैं और यह तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान ने खाड़ी के देशों पर भी हमले किए हैं। लगभग 20 देश युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। उधर युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल और गैस की 20 फीसदी आवाजाही इस मार्ग से होती है। ऐसे में भारत सहित कई देश तेल और गैस की कमी के कगार पर खड़े हैं। साथ ही साथ युद्ध के चलते तेल और गैस की आवाजाही के बाधित होने से तेल और गैस की कीमतों में भी खासी वृद्धि हुई है और यह लगातार जारी है। भारत में सरकार द्वारा एक्साईज ड्यूटी घटाकर तेल की कीमतों को स्थिर रखने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में लगातार होती वृद्धि के कारण अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि प्रारंभ हो गई है। कॉमर्शियल गैस के सिलेंडरों की कीमतों में तो पहले से ही भारी वृद्धि हो चुकी है। हालांकि रसोई गैस की कीमतों को अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन उसमें कभी भी वृद्धि हो सकती है।

दूसरी तरफ चूंकि देश की कच्चे तेल की लगभग 88 प्रतिशत पूर्ति आयात से होती है, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण भारत का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक तरफ रुपए में गिरावट हो रही है तो दूसरी तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली होता जा रहा है। युद्ध के प्रथम तीन महीनों में ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 47 अरब डालर कम हो चुका है। इन सब बातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि वे पेट्रोलियम पदार्थों के उपयोग को उत्तरोत्तर कम करने का प्रयास करें। इस कारण उन्होंने जनता से वर्क फ्रॉम होम, अधिक सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की भी अपील की है। साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए भी उन्होंने सोने की खरीद को कम करने, विदेशी यात्राओं से परहेज करने आदि के लिए भी जनता से गुहार लगाई है। इन परिस्थितियों में मई 2026 के तीसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली की महत्वपूर्ण यात्राएं आज बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हालांकि इन यात्राओं का रणनीतिक संदर्भ भी है। लेकिन माना जा रहा है कि इन यात्राओं के पीछे एक बड़ी प्राथमिकता देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग भी है। पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता और वैश्विक तेल बाजारों में उथल-पुथल के चलते यह स्पष्ट है कि भारत इस यात्रा को परंपरागत तेल की आपूर्ति और भविष्य के लिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं को बढ़ाने में सफल हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात भारत के तेल आयात का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से भारत की कुल कच्चे तेल की आपूर्ति का 11 प्रतिशत प्राप्त होता है। तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में यूएई का तीसरा स्थान है और भारत यूएई की गैस का सबसे बड़ा खरीददार है। एलपीजी के लिए भी यूएई भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी तरफ भारत द्वारा परिष्कृत पेट्रोलियम और लुब्रीकेंट का निर्यात भी यूएई में बड़ी मात्रा में होता है और इस संदर्भ में भी उसका दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारतीय कंपनियों ने बड़ी मात्रा में यूएई की ऊर्जा परिसंपत्तियों में निवेश किया हुआ है। यूएई की कंपनी मसदर ने राजस्थान में 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण के लिए समझौता किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की यात्राओं में यूएई की यात्रा प्रारंभ में शामिल नहीं थी, और अंतिम समय पर 15 मई के लिए यूएई की यात्रा को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जोड़ा गया। यात्रा क्रम में इस बदलाव को कूटनीतिक और आर्थिक हलकों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे खास यह रही कि आपातकाल में भारत के पेट्रोलियम भंडार की आवश्यकता पूर्ण करेगा और ऐसी किसी भी स्थिति में भारत को गारंटी के साथ तेल की आपूर्ति की जा सकेगी। हालांकि भारत के पास तेल के भंडारण की काफी क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी युद्धकाल में ऐसा देखा गया कि यह क्षमता युद्ध की स्थिति में अपर्याप्त है। अबूधाबी नेशनल आयल कंपनी और इंडियन आयल लिमिटेड के बीच एक सहयोग समझौता हुआ, जिससे भारत की एलपीजी आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यूएई की यात्रा में खास बात रणनीतिक प्रतिरक्षा साझेदारी का फ्रेमवर्क भी शामिल है। इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा और प्रौद्योगिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा। जलपोत मरम्मत हेतु गुजरात में एक कलस्टर भी बनाया जाएगा। यूएई द्वारा भारत में निवेश के संदर्भ में भी समझौते हुए। कुल मिलाकर भारत और यूएई के बीच आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय इसके साथ शुरू हो गया है। यह सही है कि चाहे लंबे समय से देश की अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकताएं आयातित पेट्रोलियम पदार्थों से पूरी होती रही हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में भी काफी प्रगति की है। आज देश में जितनी बिजली उत्पादन की क्षमता है, उसका 51 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली योजनाओं, न्यूक्लियर ऊर्जा आदि से आता है। इसमें देश लगातार प्रगति कर रहा है और नवकरणीय ऊर्जा क्षमता जो वर्तमान में 288 गीगावाट है, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य है। इससे न केवल भारत ऊर्जा की दृष्टि से केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि ऊर्जा की आवश्यकताएं जो अभी तक पेट्रोलियम पदार्थों से पूर्ण होती हैं, अब नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ण हो सकेंगी। पिछले कुछ वर्षों में बैटरी चलित वाहन जैसे ई-रिक्शा, कारें, छोटे और बड़े ट्रक, बस आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एक तरफ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और दूसरी ओर विद्युत चालित वाहनों में प्रगति देश को ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अल्पकाल में देश ऊर्जा की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता।

संघर्षरत रहने से ही मिलती है सफलता

जेपी शर्मा

चिंतन-मनन

आज के दौर में जीवनशैली इस कद्र जटिल हो गई है कि मनुष्य जीवन की प्रकृति प्रदत्त सहजता, संयम, सुगमता, व्यवहार कुशलता, अपनत्व, समन्वय, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, सौहार्द, सान्निध्य, मनोसंतुलन सभी कुछ नकारात्मकताग्रस्त हो गया है। बाल्यकाल की मासूम चंचलता, युवावर्ग का जोशो जुनून, वरिष्ठजनों का धैर्य, औरतों की लज्जा, पुरुषों का पुरुषत्व जैसे सभी कुछ आज के दौर की आधुनिकता, प्रगतिशील छोड़, डिजिटल युगीन उपकरणीय व्यवस्थाओं की बलिवेदी पर कुर्बान होकर अपनी पुरातन परंपरागतयुगीन अच्छाइयों की आहुति दे चुका है, नतीजतन मनोमस्तिष्क विषैला, प्रदुषित, विध्वंसक प्रवृत्तियों का शिकार होता जा रहा है। पूर्व कालखंड में जीवन का प्रतिपल भरपूर आनंद के साथ जीने वाला व्यक्ति आज आत्महत्या, कत्लोगारत, परमार्थविनाश, कामान्धता, प्रताड़ना उत्पीड़न द्वेष सरीखी गैरइनसानी मानसिकता के साथ जीवन जी रहा है या यूं कहें कि महज जीवन काट ही रहा है। मामूली सी भी विकट व विषम परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना करने का न साहस जुटा पाता है, न सामर्थ्य रखता है बल्कि पलायन प्रवृत्ति पाल लेता है। बेशक वह विधाता द्वारा दिया जीवनकाल जीने को विवश भी है और लिखी प्रारब्ध व कर्मों के प्रतिफल के अनुसार कठिनाइयों का दुख उठाने को बाध्य भी है।

अब आयु व कठिनाइयां तो ईश्वर व भाग्य के हाथ में हैं, जहां उसका कोई जोर नहीं वह बेबस है, परंतु जीवनचक्र में निर्धारित नियति को वह किस कद्र अपने चरित्र, कर्म, व्यवहार, आचरण से संवारे, निखारे यह तो उसके अपने हाथ में है, यही लेख का सार है कि जब प्रकृति प्रदत्त दी जिंदगी जीनी ही है और सभी उतार-चढ़ावों को भुगतना भी है तो उसे आखरी सांस तक सामर्थ्य अनुसार संघर्षरत रह जुझारू बने रहना ही लाजिमी है। इससे उसके जीवन के गतिरोधों में भी गतिशीलता आएगी और उसको ईश्वरीय वरदहस्त भी प्रदान होगा। प्रचलित अनमोल कहावत है कि ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करता है, पराजय से पहले मनोपराजय होने की मानसिकता कदापि न पालें। जूझेंगे तो जीत की संभावनाएं भी बनती रहेंगी, प्रभु की पवित्र वाणीयां भी यही सीख देती है कि ह्यमन के हारे हार है मन के जीते जीतह्ल अर्थात किसी समस्या को सुलझाने के प्रयास से पूर्व ही यह सोच कर बैठ जाना कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा हार की गारंटी है, मनोपराजय है,

आपके पत्र

टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं

एक समय था जब टीबी यानी क्षय रोग का नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवार में डर का माहौल बन जाता था। लोगों को लगता था कि यह बीमारी जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी और इसका इलाज संभव नहीं है। जानकारी की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण अनेक मरीज समय पर उपचार नहीं ले पाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा विज्ञान ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

आज टीबी का प्रभावी इलाज उपलब्ध है और लाखों मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि अब टीबी को लाइलाज बीमारी नहीं माना जाता, बल्कि समय पर पहचान और नियमित उपचार से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है।

कल्पना विश्वास,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।
प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website :**
www.metrorays.in **email : metrorays.ranchi@gmail.com**

न्यूज IN ब्रीफ

नर्सिंग होम का खुलना स्थानीय वासियों के लिए एक बेहतरीन पहल है : आलमगीर

साहिबगंज/बरहरवा : प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बिंदुपाड़ि पंचायत के बिशनपुर बिंदुपाड़ा बाजार में सोमवार को खुशी नर्सिंग होम का भव्य उद्घाटन किया गया।पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं फरक्का विधायक महताब शेख ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया।कार्यक्रम की शुरूआत में नर्सिंग होम प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और विशिष्ट अतिथि विधायक महताब शेख को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया।आलमगीर आलम ने उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में नर्सिंग होम का खुलना स्थानीय वासियों के लिए एक बेहतरीन पहल है।अब आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सकेगी।इससे मरीजों को इलाज के लिए बाहर भागने की जरूरत कम पड़ेगी।स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है।वहीं फरक्का विधायक महताब शेख ने डॉक्टरों और प्रबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि नर्सिंग होम को सिर्फ कमाई का जरिया न बनाया जाए।डॉक्टर पूरी निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा करें और क्षेत्र के गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष सेवा का ध्यान रखें।खुशी नर्सिंग होम के संचालक (ऑनर्स) सबीर शेख,सुनीता देवी और मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि इस अस्पताल में सर्जन,फिजिशियन,आर्थोपेडिक, गाइनोकोलॉजिस्ट सहित कई अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी।उन्होंने कहा कि जो गरीब मरीज इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होंगे उन्हें उचित और रियायती दरों पर हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।मौके पर साहिबगंज जिला अध्यक्ष बरकत खान,जिला उपाध्यक्ष नाबिद अंजुम,प्रखंड अध्यक्ष रणजीत टुडू,प्रखंड उपाध्यक्ष अनंत लाल भगत प्रखंड महासचिव निताय सरकार दौरान चौधरी मोतिउर अंसारी,मो.सबीर शेख,समीम मंसूरी सहित भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।

दो बार यहां आ चुका हूं लेकिन उस समय इतना सुंदर मंदिर परिसर नहीं था : पूर्व सांसद

साहिबगंज : भाजपा द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन के दिन एक सत्र लेने हेतु मां गंगा के पावन धरा साहिबगंज पधारे झारखंड भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद यदुनाथ पाण्डेय,प्रदेश भाजपा के कार्यसमिति सदस्य गणेश प्रसाद तिवारी एवं प्रदेश प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक प्रमोद कुमार पाण्डेय ने विश्व प्रसिद्ध चैतन्य महाप्रभु के आगमन स्थल कन्हैया स्थान का भ्रमण किया।कन्हैया स्थान आगमन के पश्चात भाजपा के मुन्ना मंडल,चंकी पाण्डेय, बैजनाथ मंडल आदि ने अंग वस्त्र पहनाकर और श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ देकर सम्मानित किया।श्री यदुनाथ पाण्डेय को वहां के पुजारी ने पूजन व आरती कराकर खीर का भोग प्रसाद वितरण किया।श्री यदुनाथ पाण्डेय पूरा मंदिर परिसर घूमकर मंत्रमुग्ध हो उठे।उन्होंने कहा कि मैं इसके पहले दो बार यहां आ चुका हूं लेकिन उस समय इतना सुंदर मंदिर परिसर नहीं था और आज यह देखकर खुशी का अनुभव कर रहा हूं।बगल में मां गंगा का कलकल स्वर और प्राकृतिक छटा का कोई मोल नहीं है।ऐसा लगता है कि जब भी मैं साहिबगंज आऊंगा,ईश्वर का दर्शन करने अवश्य जाऊंगा।

नीति कौशल से भारत के इतिहास को नई दिशा मिली : राजीव ओझा

साहिबगंज : शहर के एन आर पी सेंटर स्कूल परिसर में श्री परशुराम अखाड़ा द्वारा आचार्य चाणक्य की जयंती एवं विश्व ब्राह्मण दिवस के अवसर पर सामाजिक गोष्ठी का आयोजन किया गया।इस अवसर पर आचार्य चाणक्य और ब्राह्मण महापुरुषों को याद किया गया जिन्होंने इस देश और धर्म के लिए महान कार्य किया है।मंच पर कृष्णा शर्मा,मनोज झा और संजय तिवारी आसीन थे।वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व ब्राह्मण दिवस एवं आचार्य चाणक्य जी की जयंती भारतीय संस्कृति,ज्ञान,राष्ट्रनीति और सनातन परंपरा के गौरव को स्मरण करने का पावन अवसर है।यह दिवस केवल एक समाज विशेष का उत्सव नहीं,बल्कि ज्ञान,शिक्षा,संस्कार,त्याग और राष्ट्रसेवा की महान परंपरा का सम्मान है। भारतीय सभ्यता में ब्राह्मण समाज को सदैव ज्ञान और धर्म का मार्गदर्शक माना गया है।वहीं आचार्य चाणक्य ने अपने अद्वितीय ज्ञान दूरदर्शिता और नीति कौशल से भारत के इतिहास को नई दिशा प्रदान की।यह दिवस हमें केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता,बल्कि यह संकल्प लेने की प्रेरणा भी देता है कि हम शिक्षा संस्कार, सत्य,सेवा और मानवता के मार्ग पर चलेंगे।हमें समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए।नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और महान व्यक्तित्वों के आदर्शों से जोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और राष्ट्र निर्माण में शिक्षित एवं संस्कारी समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।हमें आचार्य चाणक्य के आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त, समृद्ध और नैतिक भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।इस अवसर पर श्री परशुराम अखाड़ा प्रमुख राजीव ओझा उपाध्यक्ष रविकांत शर्मा, युवा संयोजक अंकित पाण्डेय,बच्चन पाठक,परमानंद उपाध्याय,जगदीश शर्मा,श्रवण शर्मा,श्रीकांत ओझा आदि उपस्थित थे।

योजनाओं के लंबित कार्यों में तेजी लाएं : उपायुक्त

छात्रवृत्ति साइकिल वितरण स्वास्थ्य सहायता छात्रावास निर्माण और पीवीटीजी सर्वे कार्यों की प्रगति पर उपायुक्त ने की विस्तृत समीक्षा

संवाददाता

साहिबगंज : उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण आई०टी०डी०ए० एंव जिला कल्याण कार्यालय अंतर्गत संचालित योजना,कार्यों व पीवीटीजी समुदाय के परिवारों के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।बैठक में उपायुक्त द्वारा सर्वप्रथम जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज द्वारा संचालित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 2025-26 की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि डीएनएओ स्तर से कुल 653 छात्र-छात्राओं का आवेदन सही पाया गया है। जिन्हें जिला स्तर पर अनुमोदित किया गया। तथा प्री-मैट्रिक में कुल 76 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु जिला स्तरीय अनुमोदन समिति में अनुमोदित किया गया।वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत साइकिल वितरण योजना की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के अनुसार 20753 साईकिल प्राप्त हुई, इनमें से 18642 साइकिल को फिटिंग कर 18,623 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। वही फिटिंग हेतु 2111 साइकिल लंबित है। उपायुक्त ने साइकिलों का शीघ्र फिटिंग व सत्यापन कर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा करते हुए प्राप्त आवंटन और व्यय की स्थिति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान पाया गया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त 59 आवेदनों को सत्यापन हेतु सिविल सर्जन कार्यालय भेजा गया है। उपायुक्त ने सभी आवेदनों का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने को निर्देश दिया गया जिससे लाभुकों को समय पर सहायता उपलब्ध करायी जा सके। जबकि दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित साहों के विरुद्ध ग्राद्ध उपलब्धियों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत मामलों, ऋण वितरण तथा लाभुकों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभउपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक बिरसा मुंडा आवास योजना, सरना, मसना, जाहेरस्थान एवं हड़गड़ी घेराबंदी योजना, आदिवासी कला केंद्र एवं धुमकुड़िया भवन निर्माण योजना, मांझी थान योजना तथा कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने, कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।पी०एम० जनमन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्मित किए जा रहे मल्टीपरपज सेंटर भवनों की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 14 एमपीसी भवनों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 13 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 01 भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को शेष भवन का निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया।बैठक में डीएमएफटी मद से स्वीकृत योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 17 पीवीटीजी विद्यालयों में मॉड्यूलर किचन-सह-भोजनालय एवं शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत था, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 05 अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा संबंधित पदाधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता के साथ जल्द निमार्ण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। आवासीय विद्यालयों एवं आवासीय दिवाकालीन विद्यालयों में रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिए।समीक्षा के दौरान साहेबगंज, बड़हरवा, उधवा, बरहेट एवं पतना स्थित जनजातीय छात्रावासों में छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड क्षमता बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक के अनुसार प्राक्कलन तैयार कर उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।इसके अतिरिक्त पीवीटीजी समुदाय के परिवारों के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने, शत-प्रतिशत परिवारों को आच्छादित करने तथा अद्यतन एवं त्रुटिरहित आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री संजय कुमार दास सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर का सफल आयोजन

संवाददाता

साहिबगंज : जिले के सिद्धो-कान्हो सभागार में सीएससी,एएसके सेंटर और इंडियन पोस्टल बैंक के सहयोग से आज आधार से संबंधित विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी संदीप कुमार द्वारा किया गया। जबकि विशेष शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर के दौरान लगभग 150 लोगों की आधार से संबंधित समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया। आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि अद्यतन, बायोमेट्रिक अपडेट सहित अन्य तकनीकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया गया।शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आधार सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर सरल, सुगम एवं प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराना था। उपस्थित नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी संदीप कुमार ने बताया कि आधार से संबंधित सेवाओं को आमजन तक सुलभ एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा।जिला प्रशासन नागरिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।शिविर मे सीएससी, ए0एस0के0 केंद्र और इंडियन पोस्टल बैंक के कर्मी उपस्थित थे।

जिप सदस्य ने जल्द दूसरे खराब ट्रांसफार्मर को भी बदलने का दिया आश्वासन

संवाददाता

साहिबगंज/उधवा : प्रखंड के उत्तरी बेगमगंज पंचायत अंतर्गत मिस्त्री टोला गांव में पिछले करीब 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप थी। भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम में बिजली नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को गांव में नया 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य सहनारा बीबी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अजरूद्दीन शेख तथा मुखिया प्रतिनिधि शिवपति मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान जिप सदस्य सहनारा बीबी ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था और घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा समस्या की जानकारी दिए जाने के बाद विधायक के प्रयास से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया। उन्होंने आगे बताया कि गांव में एक अन्य ट्रांसफार्मर भी खराब है, जिसे जल्द ही बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके।ट्रांसफार्मर चालू होते ही स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों एवं विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर वार्ड सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनुकूल चंद्र मिश्रा ने अपना 74 वा जन्मोत्सव मनाया

संवाददाता

साहिबगंज : कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने अपना 74 वा जन्मदिन सोमवार को अपने निजी होटल अभिनव में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।इस अवसर पर परिवार,मित्रों,शुभचिंतकों एवं गणमान्य लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ,सुखद व उज्ज्वल भविष्य की कामना की।इस दौरान वहाँ मौजूद सभी लोगो ने जन्मदिन समारोह में केक काटकर खुशियां साझा की गईं।उपस्थित लोगों ने उनके सामाजिक कार्यों,मिलनसार स्वभाव एवं समाज के प्रति योगदान की सराहना की।हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्मदिन को सादगी और सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया गया। समारोह में उपस्थित लोगों ने उन्हें फूल-मालाएं एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्तियों,मित्रों एवं रिश्तेदारों ने फोन,सोशल मीडिया तथा व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर शुभकामनाएं दीं।पूरे दिन शुभचिंतकों का उनके आवास पर आना-जाना लगा रहा,जिससे माहौल उत्सवमय बना रहा।मौके पर सेवानिवृत शिक्षक कालू यादव,अधिवक्ता जनार्दन प्रसाद,नित्यानंद गुप्ता,मो अल्ताफ हुसैन,मो समसूल,सुनील पासवान,अजय कुमार यादव पत्रकार बचन कुमार पाठक,अरविन्द कुमार यादव,सहेंद्र प्रसाद,,पंकज वर्मा,चंदन कुमार,वार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित स्वदेशी,जिला विकास समिति के अध्यक्ष अभिक्रम सिंह,मुर्शाद अली सहित अन्य मौजूद थे।

राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में एक बार फिर साहिबगंज के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन

साहिबगंज : राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में एक बार फिर साहिबगंज के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया हैं।इसी कड़ी में आज जारी हुई आई आई टी परीक्षा के परिणाम में साहिबगंज के मयंक चौधरी ने अपनी पहली प्रयास में 680 रैंक लाकर साहिबगंज का नाम रौशन किया हैं। पढ़ने में बच्चे से मेधावी रहे मयंक चौधरी पुरानी साहिबगंज निवासी मनोज चौधरी और कंचन देवी के पुत्र हैं। उसकी इस सफलता से पुरा परिवार में खुशियों का लहर हैं।चाचा मिथिलेश चौधरी जो विशेष शाखा में एएसआई में पदास्थापित हैं बताते हैं की मयंक बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रहा। मयंक के पिता मनोज चौधरी पेशे से इंजीनियर हैं।इसलिए उसे अपने पिता से प्रेरणा मिला.मयंक 10 वीं की पढ़ाई हैदराबाद के भारती विद्या स्कूल और 12वीं की पढ़ाई गाजियाबाद से किया हैं.

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस की अहम बैठक

एसआईआर मैपिंग व अनपेजिंग को लेकर बीएलए 2 कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश

संवाददाता

साहिबगंज/बरहरवा : पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के इस्लामपुर स्थित आवास प्रांगण में कांग्रेस पार्टी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता बरहरवा प्रखंड अध्यक्ष रंजीत टुडू ने की।इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों व पंचायतों के अध्यक्षों,पार्टी कार्यकताओं और नव-नियुक्त बीएलए 2 बूथ लेवल एजेंटने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट एंड रजिस्ट्रेशन मैपिंग और अनपेजिंग प्रक्रिया को लेकर बीएलए 2 कार्यकताओं को प्रशिक्षित करना तथा विशेष दिशा-निर्देश देना था।बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में बनाए गए बीएलए 2 का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य यह होना चाहिए कि क्षेत्र के किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम एस आई आर सूची से न छूटे।उन्होंने कहा,आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है या जिन्हें अपना नाम खोजने में परेशानी आ रही है। बीएलए-2 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीएल ओ बूथ लेवल ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि हर सही व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज हो। बीएलए खुद को सिर्फ एक कार्यकर्ता न समझें,वे पार्टी की रीढ़ हैं और उन्हें पूरी निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाना है।बैठक में उपस्थित मास्टर ट्रेनर हीरालाल साहा ने कार्यकताओं को तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि मैपिंग और अनपेजिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा,सभी बीएलए-2 अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर डेटा का बारीकी से मिलान करें।अनपेजिंग और मैपिंग के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए ट्रेनर्स हमेशा उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शत-प्रतिशत त्रुटिहीन काम हो।जिला अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान ने कार्यकताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती आई है। एस आई आर मैपिंग आम जनता से जुड़ा एक गंभीर विषय है।इसलिए सभी कार्यकर्ता और पंचायत अध्यक्ष चुनावी मोड में आकर धरातल पर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी जरूरतमंद इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष रंजीत टुडू ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के कुशल मार्गदर्शन में बरहरवा प्रखंड के सभी पंचायतों और मंडलों में इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा।उन्होंने कहा,प्रखंड कमेटी पूरी तरह से सक्रिय है।सभी मंडल और पंचायत अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में बीएलए-2 के कार्यों की निगरानी करेंगे ताकि शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए निदेशों का अक्षरश पालन हो सके।बैठक में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉ तनवीर आलम बरहरवा प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष अशोक कुमार दास,रैसूल आलम,बरहरवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता,बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के अध्यक्ष,मंडल अध्यक्ष एवं बीएलए2 मुख्य रूप से उपस्थित थे।

आईफा कॉन्क्लेव में छाया अरुणाभ कुमार और करण जौहर का खास मोमेंट

समय के साथ द वायरल फीवर यानी टीवीएफ देश के सबसे बड़े कंटेंट प्रोड्यूसर्स में से एक बनकर उभरा है, जिसने अपने रिलेटेबल शोज के जरिए डिजिटल कंटेंट की दुनिया में खास पहचान बनाई है। इसके फाउंडर अरुणाभ कुमार का विजन हमेशा से उस युवा पीढ़ी से जुड़ने का रहा है, जो पारंपरिक टेलीविजन मनोरंजन से दूर होती जा रही थी। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जो आज कंटेंट की दुनिया में लगातार सफलता हासिल कर रहा है। हाल ही में आईफा कॉन्क्लेव में एक खास पल देखने को मिला, जब एंटरटेनमेंट जगत की दो क्रिएटिव ताकतें, अरुणाभ कुमार और फिल्ममेकर करण जौहर, एक साथ नजर आए।

जहां करण जौहर ने बड़े पर्दे पर रोमांस को नई पहचान दी और उनका आइकॉनिक डायलॉग प्यार दोस्ती है एक पूरे दौर की परिभाषा बन गया, वहीं अरुणाभ कुमार ने द वायरल फीवर के जरिए कंटेंट की दुनिया में एक नई क्रांति लाने का काम किया।

अरुणाभ कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर गोविक के चीफ ग्रोथ ऑफिसर वर्गब बक्शी और फिल्ममेकर करण जौहर के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा-

ह्लवर्गब कंटेंट बिजनेस के टीएएम के बावजूद डी2सी से कंटेंट की दुनिया में स्विंग कर रहे हैं । अरुणाभ कुमार ने द वायरल फीवर यानी टीवीएफ की शुरूआत यूट्यूब वीडियोज से की थी और आज यह एक ग्लोबल कंटेंट फोर्स बन चुका है, जिसके शोज और फिल्में ओटीटी स्पेस पर छाए हुए हैं। कंपनी ने परमानेंट रूममेट्स , पिचर्स, ट्रिपलिंग, एस्पिरेंट्स , पंचायत, कोटा फैक्ट्री, गुल्लकसमेत कई बड़े और सफल शोज दिए हैं। अब टीवीएफ फिल्म्स की दुनिया में भी कदम रख रहा है और व्वान जैसी फिल्म लेकर आ रहा है।

वेब कंटेंट की दुनिया में क्रांति लाने से लेकर आइकॉनिक कहानियां गढ़ने और नए टैलेंट को मंच देने तक, टीवीएफ के फाउंडर अरुणाभ कुमार भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक मजबूत और अलग पहचान बन चुके हैं। उनका सफर विजन, इनोवेशन और दमदार स्टोरीटेलिंग की ताकत को दर्शाता है।

इसके अलावा, प्राइम वीडियो प्रेसनेट्स इवेंट में भी टीवीएफ पूरी तरह छाया रहा, जहां उसने एक के बाद एक बड़े ऐलान कर सभी का ध्यान खींच लिया।

डॉन 3 विवाद में आया नया मोड़, रणबीर सिंह के समर्थन में कोर्ट पहुंचे दिग्गज प्रोड्यूसर टीपी. अग्रवाल, बैन कल्चर को दी चुनौती

फिल्म डॉन 3 को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ उठी बैन की मांग के बीच बॉलीवुड के वरिष्ठ निमार्ता टीपी अग्रवाल उनके समर्थन में सामने आये हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने बॉम्बे सिविल कोर्ट का रास्ता अपनाया है, जिससे इंडस्ट्री की प्रमुख संस्था एफडब्ल्यूआईसीई पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है।

करीब 17 वर्षो तक एफडब्ल्यूआईसीई के अध्यक्ष रह चुके टीपी. अग्रवाल ने अपनी याचिका में फिल्म इंडस्ट्री में जारी बैन कल्चर और नान-कोऑपरेशन जैसे आदेशों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी संगठन या ट्रेड बॉडी को किसी कलाकार या तकनीशियन की पेशेवर स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

इसी के साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि कोई संस्था यह तय नहीं कर सकती की इंडस्ट्री के सदस्य किस कलाकार के साथ काम करे या न करें। ऐसे फैसले किसी व्यक्ति के करियर और काम काम करने के अधिकत को प्रभावित कर सकते हैं।

मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे सिविल कोर्ट ने एफडब्ल्यूआईसीई और आईएमपीपीए दोनों को नोटिस जारी किया है। अब इस संगठनों को अदालत के समक्ष अपने रुख और फैसलों का आधार स्पष्ट करना होगा।

परफेक्ट बॉडी की चाह में खुद पर डाला था जरूरत से ज्यादा दबाव, तापसी पन्नू ने दी लड़कियों को सलाह,जैसी हो वैसी रहो

बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने हाल ही में अपने शरीर और फिटनेस को लेकर किये गए संघर्षो के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब वह फ्लैट टमी पाने को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहती थीं और इसी वजह से उन्होंने खुद पर जरुरत से ज्यादा दवाब बना लिया था।

सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा से ही फिट रहना पसंद है और बचपना से ही वो काफी मेहनत करती आई हैं लेकिन पेट के निचले हिस्से के मोटापे को लेकर हमेशा परेशान रहती थीं। इसे कम करने के लिए ही उन्होंने लगातार और बेहद कठिन वर्कआउट करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उन्हें लगा कि शायद वो कुछ गलत कर रही हैं क्योकि जरुरत से ज्यादा की गई मेहनत भी अभी परेशानी में डाल देती है। अभिनेत्री के मुताबिक, जब शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जाता है तो वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। ऐसे में शरीर पानी को रोककर रखने लगता है, जिससे सूजन और फुलाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोग इसे सिर्फ फैट समझ लेते हैं, जबकि इसके पीछे अन्य शारीरिक कारण भी हो सकते हैं।

इसी के साथ तापसी ने बताया कि हर एक महिला का शरीर अलग होता है। जरूरी नहीं की सबका शरीर एक जैसा लगे। उन्होंने बताया कि उनको यह एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगा कि जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। शरीर में छोटा-मोटा बदलाव पूरी तरह से सामान्य है।

इसी के साथ तापसी पन्नू में लड़कियों को सलाह देते हुए कहा कि शरीर को फिट रखना जरुरी है लेकिन ज्यादा फिट होने के चक्कर में अपने शरीर पर ज्यादा दवाब न डालें। अपने शरीर को समझना, उसकी जरूरतों का सम्मान करना और खुद को स्वीकार करना ही असली फिटनेस और आत्मविश्वास की पहचान है।

उम्र सिर्फ नंबर है ! 59 की उम्र में भी धक-धक गर्ल माधुरी ने पिंक साड़ी पहन जीता सबका दिल

बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई माधुरी दीक्षित की अदाओं पर दीवाना है। 59 की उम्र में भी धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित की खूबसूरती कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल इन दिनों वो अपनी नेटफ्लिक्स मूवी मां-बहन को लेकर काफी चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिन्हे देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। ट इस साड़ी पर की नाजुक फूलों की कढ़ाई इसे बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लुक दे रही है। इस साड़ी की खास बात ही इसकी सादगी है, जो इसे और भी ज्यादा सुन्दर बना रही है। इसके साथ माधुरी ने मैचिंग का पिंक कलर का हाई-नेक और स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ है। उनके ब्लाउज का स्टाइल माधुरी के पूरे लुक को ट्रेडिशनल के साथ-साथ मॉडर्न लुक भी दे रहा है। इसी के साथ अगर उनके हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने बन किया हुआ है। बहुत ज्यादा भारी-भरकम एयररिंग न पहनते हुए उन्होंने सिंपल से स्टेटमेंट ईयररिंग्स पहने हैं, जो उनकी खूबसूरती को चार चाँद लगा रहे हैं।

गवर्नर के ट्रेलर ने जीता छात्रों का दिल, दमदार विजुअल्स से लेकर इतिहास के अहम सबक तक

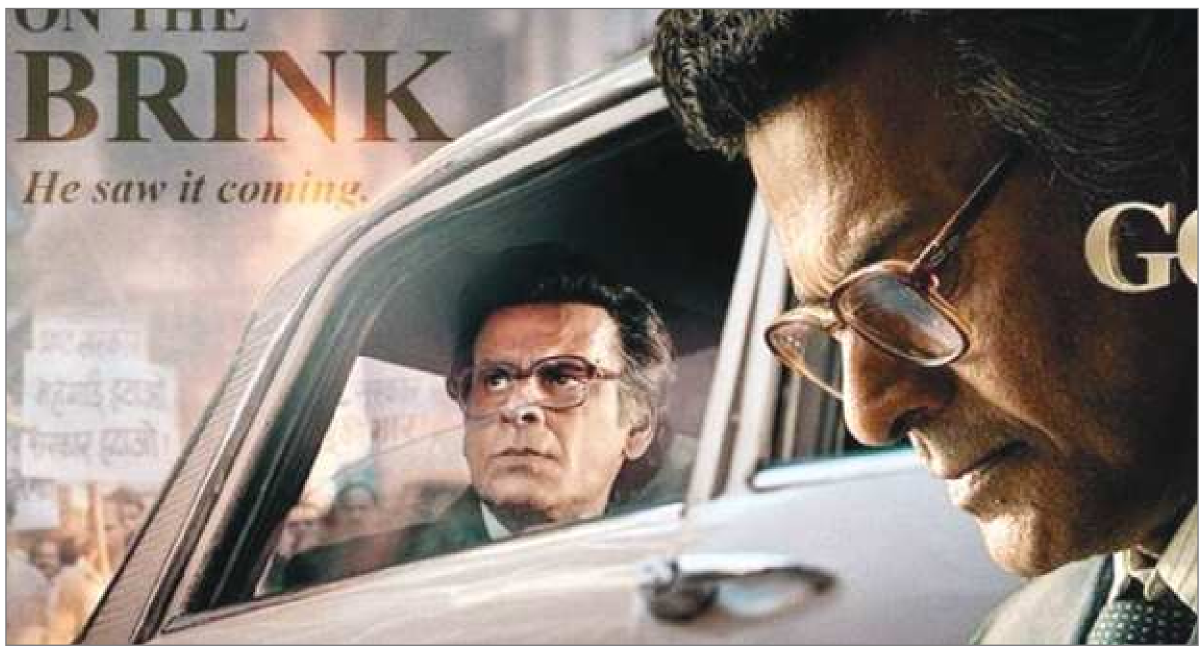

साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक गवर्नर में मनोज बाजपेयी के साथ अदा शर्मा नजर आएंगी और फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पहले से ही देखने को मिल रहा है। यह फिल्म भारत के आर्थिक इतिहास के एक बेहद अहम लेकिन कम चर्चित अध्याय को दिखाती है और 1990 के वित्तीय संकट को बड़े पर्दे पर बेहद दिलचस्प और प्रभावशाली अंदाज में पेश करती है। हाल ही में रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर दर्शकों, खासकर छात्रों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बड़ी संख्या में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स शामिल हुए थे।

मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कई मैनेजमेंट स्टूडेंट्स नजर आए और अब उनकी दमदार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। छात्रों ने ट्रेलर के हर पहलू की तारीफ की और कहा कि जिस तरह फिल्म भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को बड़े पर्दे पर लेकर आई है, वह बेहद प्रभावशाली है। खासतौर पर मनोज बाजपेयी की दमदार परफॉर्मेंस ने उन्हें काफी प्रभावित किया और फिल्म को लेकर उनका उत्साह और बढ़ा दिया।

छात्रों ने यह भी कहा कि गवर्नर ऐसी फिल्म है जो नई पीढ़ी को सही मायनों में शिक्षित करेगी, क्योंकि आज के समय में कई लोग अपने देश के इतिहास और आर्थिक संघर्षों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। उन्होंने फिल्म को मस्ट वॉच बताया और फिल्ममेकर विपुल अमृतलाल शाह की सराहना की कि उन्होंने सिनेमा के जरिए लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण कहानी चुनी।

वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा,,दमदार प्रतिक्रियाओं से लेकर सोचने पर मजबूर कर देने वाली बातचीत तक, गवर्नर का ट्रेलर हर जगह छात्रों से गहराई से जुड़ रहा है।

हर प्रतिक्रिया के साथ कहानी के लिए उत्साह, सराहना और प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है।

गवर्नर 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में: सच्ची घटनाओं पर आधारित गवर्नर 1990 के दशक में भारत को हिला देने वाले आर्थिक संकट की गहराई में उतरती है। तनाव, सत्ता और राजनीतिक ड्रामे से भरपूर इसका ट्रेलर संकट और संघर्ष की दुनिया की एक रोमांचक झलक पेश करता है। नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी फिल्म में गवर्नर की भूमिका में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने दमदार और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस से किरदार को बेहद खास बना दिया है।

वैभव को नेचुरल गेम खेलने दें, तेंदुलकर बोले सूर्यवंशी बेहद खास, टेस्ट के लिए न करें जल्दबाजी

> सिर्फ गेंद को हिट करने की ताकत ही नहीं, बल्कि उनकी कलाई का काम भी कमाल का है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सचिन ने कहा, मैदान के हर कोने में शॉट खेलने के लिए आपकी कलाई मजबूत होनी चाहिए।

मुंबईः पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने युवा बैटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, वैभव वाकई बेहद खास खिलाड़ी हैं। उनमें मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की अद्भुत कला है। तेंदुलकर ने सलाह दी कि कोई भी उनके नेचुरल गेम के साथ छेड़छाड़ न करें। मुंबई में क्रिकइन्फो ऑनर्स इवेंट में तेंदुलकर को 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल मेंस बैटर चुना गया। तेंदुलकर ने कहा, आज सभी वैभव की बात कर रहे हैं। मैंने भी उन्हें बैटिंग करते हुए देखा है। उनमें कुछ बहुत खास बात है। सिर्फ गेंद को हिट करने की ताकत ही नहीं, बल्कि उनकी कलाई का काम भी कमाल का है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सचिन ने कहा, मैदान के हर कोने में शॉट खेलने के लिए आपकी कलाई मजबूत होनी चाहिए।

वह सिर्फ हवा में बल्ला नहीं घुमा रहे। वे बाकी खिलाड़ियों की तुलना में गेंद की लाइन और लेंथ को जल्दी भांप लेते हैं और आसानी से बाउंड्री पार करा देते हैं। तेंदुलकर ने कहा कि वह भी वैभव को टेस्ट क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वह जैसे हैं, वैसे ही रहें। टेस्ट में अनुभव के साथ वे चुनौतियों से निपटना सीख जाएंगे। वैभव एक ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है। मैं उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहूंगा।

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को बेस्ट ग्राउंड और पिच अवार्ड, एचपीसीए को मिला 25 लाख रुपए का पुरस्कार

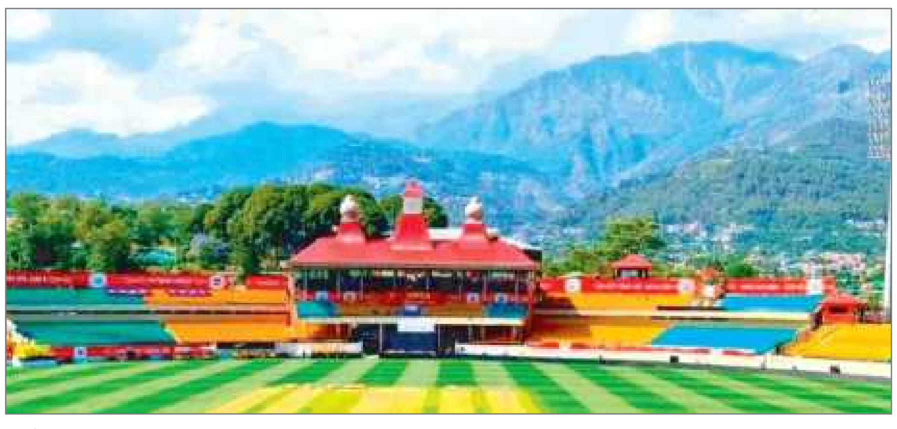

धर्मशालाः हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ने एक बार फिर देश-दुनिया में अलग पहचान बनाई है। आईपीाएल-2026 में धर्मशाला के मैदान को बेस्ट ग्राउंड एंड पिच ऑफ द सीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए एचपीसीए को 25 लाख रुपए की इनामी राशि से सम्मानित किया गया। इससे पहले वर्ष 2024 में भी स्टेडियम को साढ़े 12 लाख रुपए का पुरस्कार मिल चुका है, जबकि पिछले सीजन में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मैच स्थगित होने से धर्मशाला वंचित रह गया था। गौर हो कि धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल के तीन महत्वपूर्ण मुकाबलों सहित क्वॉलिफायर-1 मैच भी खेला गया था।

इसमें पिच व मैदान की खिलाड़ियों सहित हर ओर प्रशंसा देखने को मिली। अब धर्मशाला स्टेडियम के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। यह उपलब्धि मैदान की बेहतरीन गुणवत्ता, उत्कृष्ट पिच तैयारियों और पर्दे के पीछे दिन-रात मेहनत करने वाले क्यूरेटरों, ग्राउंड्समैन और प्रबंधन टीम की मेहनत का परिणाम मानी जा रही है। उधर, एचपीसीए के महासचिव मनुज शर्मा ने बताया कि आईपीएल-2026 में मिला यह सम्मान हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

चैंपियन आरसीबी को 20 करोड़, उपविजेता टीम गुजरात टाइटंस भी मालामाल, मिले 12.50 करोड़

अहमदाबादः रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने लगातार दूसरे सीजन आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। चैंपियन बनने पर रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली, जबकि रनरअप गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए से संतोष करना पड़ा। व्यक्तिगत पुरस्कारों में राजस्थान के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का दबदबा रहा। उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल अपने नाम किया। वैभव को मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन समेत कुल पांच अवॉर्ड मिले। इनसे उन्हें 45 लाख रुपए और एक कार मिली। वहीं, गुजरात के कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की।

रजत पाटीदार बोले, आरसीबी की जीत भगदड़ में जान गंवाने वाले फैंस को समर्पितः आईपीएल खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने अपनी जीत उन फैंस को समर्पित की, जिन्होंने पिछले साल बंगलुरु की भगदड़ में जान गंवाई थी। कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, वे सिर्फ फैंस नहीं, बल्कि आरसीबी के परिवार का हिस्सा थे। 32 साल के पाटीदार ने कहा, जब ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं, तो बहुत दुख होता है। एक तरफ टीम सेलिब्रेट कर रही होती है, दूसरी ओर फैंस की जान चली जाती है। जब भी मैं विराट भाई को देखता हूं, वे हमेशा टीम और खिलाड़ियों के लिए मौजूद रहते हैं।

आरसीबी नहीं करेगी विक्ट्री परेड

अहमदाबादः आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतने के बावजूद बंगलुरु में विक्ट्री परेड नहीं निकालने का फैसला किया है। एक सूत्र ने बताया कि शहर में सार्वजनिक समारोहों को लेकर पहले से लागू दिशा-निदेर्शों का पालन किया जाएगा। बंगलुरु में बड़े समारोह की संभावना नहीं है। बंगलुरु पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि आरसीबी की जीत पर सडक पर जश्न, पटाखेबाजी, हुड़दंग की अव्यवस्था न फैलाएं।

शिक्षा को कारोबार बनाना सभी बुराइयों का आधार

नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर उसकी गलतियों के लिए छात्रों से शुल्क वसूली को लूट करार देते हुए कहा है कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय कारोबार बना दिया जाता है, तो उससे अनेक बुराइयां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आएं, तो उसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। डिजिटल स्कैन कॉपी, री-टोटलिंग और री-इवैल्यूएशन के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है। अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच कराने के लिए एक छात्र को हजारों रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों का बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है। गलती सीबीएसई करती है और इसकी सभी बच्चे को मिलती है और सरकार इससे कमाई करती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब शिक्षा को सेवा नहीं, बल्कि कारोबार बना दिया जाता है तो गलतियां सुधरने के बजाय व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चों को अपने समय, आत्मविश्वास और भविष्य से चुकानी पड़ती है। गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रति, पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुल्क पर उपलब्ध कराने को लेकर हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई है, जिसे लेकर श्री गांधी ने यह टिप्पणी की है।

मर्जी से वेश्यावृत्ति अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दी नसीहत, कानून भी बताया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा है कि अगर कोई भी बालिग अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करती है, तो इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार करने और उन्हें प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कॉमर्शियल सेक्स के लिए मानव तस्करी की जाती है और किसी को धोखे से या फिर मजबूर करके सेक्स करवाया जाता है, तो ऐसे केस में इमोरल ट्रैफिक एक्ट लागू होता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना की बैंच ने साफ कह दिया है कि अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करना गैरकानूनी नहीं है। वहीं वेश्यालय या कोठे चलाना गैरकानूनी है। बता दें कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में बनाया गया था।

इसके तहत कई धाराएं हैं और कोठे और वेश्यालय चलाने का अपराध बताया गया है। इस एक्ट की धारा 3 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति देह व्यापार के लिए अपनी जगह को किराए पर देता है या फिर उपयोग की अनुमति देता है, तो उसे एक से तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसकी धारा-4 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्स वर्कर की कमाई का इस्तेमाल करता है, तो यह अपराध है। यह धारा सेक्स वर्कर के परिवार के लोगों पर भी लागू होती है। धारा-5 में कहा गया है कि जबरदस्ती, बहलाकर या फिर मजबूर करके किसी को देह व्यापार के लिए मजबूर करना भी अपराध है। धारा-7 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान या किसी धार्मिक स्थान के 200 मीटर के दायरे में सेक्स वर्क करना अपराध है। हालांकि इस कानून में कहीं भी सहमति से सेक्स का जिक्र नहीं किया गया है।

ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोकी, होर्मुज फिर बंद करने की तैयारी, लेबनान पर हमलों के बाद लिया फैसला

एजेंसियां/तेहरान: ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता कथित तौर पर निलंबित कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने सोमवार को मध्यस्थों के जरिए अमरीका के साथ हो रहे संदेशों के आदान-प्रदान रोक दिए हैं। ईरान का यह कदम क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि के बीच आया है, जो तेहरान और वॉशिंगटन के बीच राजनयिक प्रयासों को जटिल बना सकता है। इससे दोनों देशों के बीच आठ अप्रैल से जारी कमजोर सीजफायर के टूटने और फिर से लड़ाई शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल की ओर से लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान में लड़ाई रुकना युद्धविराम की मुख्य शर्तों में से था। इजरायल ने लेबनान समेत कई मोर्चों पर युद्धविराम का बार-बार उल्लंघन किया है।

इस रवैये से नाराज ईरानी वातार्कारों की टीम मध्यस्थों के जरिए अमेरिका से बातचीत और संदेशों के आदान-प्रदान को रोक रही है। ईरान ने होर्मुज में भी फिर से सख्ती से बंदी का संकेत दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोमवार शाम को अपने एक ट्वीट में इजरायल की ओर से लेबनान में किए जा रहे हमलों पर गुस्सा जताया है। उन्होंने साफ कहा कि लेबनान में हमलों को हम सभी मोर्चों पर युद्धविराम का उल्लंघन मानेंगे। उनके इस बयान के कुछ घंटे बाद ही ईरान की ओर से बातचीत रोकने की बात सामने आई है।

ईरान के समर्थन में कतर :

दोहा: होर्मुज में ईरानी टोल व्यवस्था को कतर ने जायज ठहराया है। कतर के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थायी तौर पर जो टोल व्यवस्था है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं स्थायी टोल व्यवस्था के खिलाफ हूं, इसका कतर हर जगह विरोध करेगा। कतर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ईरान और अमरीका के बीच होर्मुज खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। कतर पर्दे के पीछे इस डील का नेतृत्व कर रहा है।

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर फटने से गिरा मकान 6 लोग मलबे से निकाले गए, सर्च-रेस्क्यू जारी

नई दिल्ली : दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। भलस्वा डेरी के पास स्थित मुकुंदपुर-क्क के ईशु विहार में एक मकान में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होने के बाद पूरा घर ढह गया। हादसे के समय मकान में मौजूद कई लोगों के मलबे में दब जाने की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस, दमकल विभाग और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, सुबह 9:37 बजे मुकुंदपुर-।। के ईशु विहार, गली नंबर-1 से धमाके और मकान गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी गिरिराज ने बताया कि शुरूआती जांच में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट को हादसे का कारण माना जा रहा है। विस्फोट के चलते करीब 250 वर्ग गज में फैला एक मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया। राहत दल ने अब तक मलबे से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इनमें दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दो महिलाएं भी बचाए गए लोगों में शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, मकान में कुछ मजदूर अपने परिवारों के साथ रहते थे। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी अन्य व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की संभावना नहीं दिख रही है, हालांकि एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान जारी रखा गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया में रक्षा सहयोग को नई मजबूती दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में दिए

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों को नई उड़ान देने के लिए सोमवार को नई दिल्ली में एक दूसरी द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, सैन्य सहयोग, रक्षा उद्योग, सह-विकास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। बैठक के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और इंटिग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के रक्षा संबंधों में विकास की अपार संभावनाएं हैं।

श्री सिंह ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ मेरी एक बेहतरीन बैठक हुई। हमने मिलकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की और इसे और आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आज की चर्चा के दौरान, मैं इस नीतिगत दस्तावेज और भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास की संभावनाओं पर आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूं।

भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक रूप से एकजुट: वहीं रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से एकजुट हैं और दोनों देश समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से समुद्री क्षेत्र में और अधिक काम कर रहे हैं और हम अपनी नियमित बैठक में इस बारे में बात करेंगे। गौरतलब है कि यह महत्त्वपूर्ण बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक रणनीतिक चचाओं का केंद्र बना हुआ है। दोनों देशों के बीच होने वाली यह वार्ता केवल औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा साझेदारी की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी मानी जा रही है।

इन मुद्दों पर चर्चा: रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने, दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यासों को नई गति देने तथा रक्षा उद्योग में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा, जिससे दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिल सके।क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी दोनों नेता विचार-विमर्श करेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मुक्त नौवहन सुनिश्चित करने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा इस संवाद का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होगी।

राबड़ी देवी से बंगला खाली कराने के आदेश पर आरजेडी का हमला, कोर्ट जाने के संकेत

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की सोमवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर बदले की राजनीति के तहत यह कदम उठाने का आरोप लगाया। पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला, जिसमें वर्तमान में राबड़ी और उनका परिवार रह रहा है, हाल में बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। नंद किशोर को कुछ हफ्ते पहले 21 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास भी आवंटित किया गया था। राजद के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले विपक्षी दलों को निशाना बना रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, लोकतंत्र की खूबसूरती सरकार की कमियों को उजागर करने में है। अगर सरकार कोई गलती करती है, तो विपक्ष का दायित्व है कि वह उसे जवाबदेह बनाए। हालांकि, बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन चाहता है कि विपक्ष हर बात पर सरकार की हां में हां मिलाए, वरना उसे विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है।ꝛ सिद्दीकी ने दावा किया कि बिहार गरीबी और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों के समाधान के बजाय विपक्ष को निशाना बनाने में व्यस्त है। उन्होंने 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास और उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को मिलाकर 'लोक सेवक आवास' बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। सिद्दीकी ने कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि दोनों बंगलों को मिलाकर संयुक्त मुख्यमंत्री आवास क्यों बनाया गया और उसका नाम 'लोक सेवक आवास' क्यों रखा गया, जबकि उपमुख्यमंत्री अन्य बंगलों में रह रहे हैं।

लॉन्च होते ही ठप हुआ सीबीएसई का री-इवेल्यूएशन पोर्टल, छात्रों को हुई परेशानी, बोर्ड ने दोबारा किया एक्टिव

CBSE
RE-EVALUATION PORTAL
NOT LIVE
BANK
IIT

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन पोर्टल लॉन्च होते ही तकनीकी खामियों का शिकार हो गया। करीब चार दिन के इंतजार के बाद पोर्टल के सक्रिय होने से छात्रों को राहत मिली थी, लेकिन कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। हालांकि, बोर्ड का दावा है कि पोर्टल को दोबारा सक्रिय कर दिया गया है।

छात्रों के अनुसार, लॉगिन विवरण दर्ज करने के बाद स्क्रीन फ्रीज हो रही थी, जिससे आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। कई छात्रों ने पोर्टल में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। वहीं, कुछ छात्रों ने लॉगिन संबंधी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई है।

पोर्टल में आई इन तकनीकी दिक्कतों के बाद छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। यह समस्या ऐसे समय सामने आई है, जब बोर्ड की ओर से पोर्टल लॉन्च को लेकर कई बार आश्वासन दिए जा चुके थे। छात्रों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद सेवा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही समय में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बताया जा रहा है कि इस समस्या से 4,04,319 से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं, जिन्हें इस वर्ष अंकों के सत्यापन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना है।

सीबीएसई की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अनुमान जताया था कि मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देखने वाले लगभग हर पांच में से एक छात्र सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके आधार पर करीब 80 हजार आवेदन मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी। कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद से ही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सवालों के घेरे में रही है। छात्रों और अभिभावकों ने भुगतान गेटवे में खराबी, अतिरिक्त शुल्क कटने, रसीद न मिलने, लॉगिन संबंधी समस्याओं तथा स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच में कठिनाइयों की शिकायत की है। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां धुंधली या अधूरी थीं। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि उपलब्ध कराई गई प्रतियां उनके मूल उत्तरों से मेल नहीं खाती थीं।

सरकार बदलने जा रही होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष, लॉन्च करेगी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स

नई दिल्ली : सरकार थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 करने जा रही है। इसके साथ ही उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) भी लॉन्च करने जा रही है, जिसे भारत की महंगाई मापने की प्रणाली को आधुनिक और अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने इस विषय पर मंगलवार को मीडिया को ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित किया है, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो संबोधित करेंगे।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा, हमने डब्ल्यूपीआई 2022-23 के आंकड़ों का उपयोग किया है, जो हमें आंतरिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों में कोई संशोधन न करना पड़े। हमें उम्मीद है कि ये आंकड़े अगले कुछ सप्ताह में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि संशोधित श्रृंखला में इसे बदलकर 2022-23 कर दिया जाएगा।

सौरभ गर्ग ने कहा कि नया सूचकांक शुरू होने के बाद भी डब्ल्यूपीआई से आउटपुट पीपीआई में बदलाव तुरंत नहीं किया जाएगा। सरकार पहले नई श्रृंखला की स्थिरता और विश्वसनीयता का अध्ययन करेगी, उसके बाद ही इसे व्यापक स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डब्ल्यूपीआई और आउटपुट पीपीआई के बीच बहुत अधिक अंतर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए पहले से ही ऐसी पद्धति अपनाई जाती है जो दोनों के बीच अंतर को सीमित रखती है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही सांख्यिकी मंत्रालय ने 2022-23 आधार वर्ष के साथ संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जारी किया था।

मंत्रालय ने बताया था कि मूल्य आधारित वस्तुओं की गणना के लिए नए आधार वर्ष वाले अद्यतन डब्ल्यूपीआई डिफ्लेटर का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। इस साल फरवरी में सरकार ने कहा था कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधार वर्ष 2022-23 किया जा रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार वर्ष 2024 किया जा रहा है और आईआईपी का आधार वर्ष भी 2022-23 किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की सांख्यिकीय प्रणाली का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में संशोधन का काम भी जारी है। जब तक नया डब्ल्यूपीआई उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा डब्ल्यूपीआई का उपयोग डिफ्लेटर के रूप में किया जाता रहेगा। इसके अलावा, मंत्रालय निकट भविष्य में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। पीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है, जिन्हें उत्पादक खरीदते और बेचते हैं। इससे उत्पादन स्तर पर कीमतों के रुझान को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और महंगाई के आकलन को अधिक सटीक बनाया जा सकता है।

न्यूज IN ब्रीफ

ग्राम रोजगार सेवक ललन प्रजापति के आश्रितों को मनरेगा कर्मियों ने सौंपा 1.31 लाख की सहयोग राशि

मेदिनीनगर /पलामू : झारखण्ड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ, पलामू जिला कमिटी के नेतृत्व में जिले भर के मनरेगा कर्मियों ने एकजुटता एवं मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए दिवंगत ग्राम रोजगार सेवक स्व० ललन प्रजापति के आश्रित परिवार को ₹1,31,000 (एक लाख इकतीस हजार रुपये) की सहयोग राशि प्रदान की।

विदित हो कि पांडू प्रखंड के ग्राम रोजगार सेवक स्व० ललन प्रजापति का दिनांक 28 मार्च 2026 को हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी।उनके निधन के बाद परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उनके परिवार में बीमार पत्नी, एक पुत्री एवं एक पुत्र हैं, जिनके समक्ष आजीविका, शिक्षा एवं भविष्य की गंभीर चुनौतियाँ सामने खड़ी हो गई हैं।

दिवंगत साथी के पैतृक आवास सीलदिली पहुंचकर संघ के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश महामंत्री विकास पांडेय, संगठन मंत्री सचिन अख्तर हुसैन, जिला प्रवक्ता मनोज चौबे तथा पांडू प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा राम सहित जिले के सभी प्रखंड अध्यक्षों एवं सैकड़ों मनरेगा कर्मियों ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की तथा संघ की ओर से ₹1।31 लाख की सहयोग राशि उनके आश्रितों को सौंपी।

इस अवसर पर संघ के नेताओं ने कहा कि स्व० ललन प्रजापति ने लगभग 19 वर्षों तक मनरेगा के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका निधन केवल उनके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे मनरेगा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। संघ उनके परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़ा है और जिला प्रशासन से भी अनुरोध करेगा कि परिवार को उपलब्ध सभी सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सहयोग राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि पूरे मनरेगा परिवार की आत्मीय श्रद्धांजलि एवं एकजुटता का प्रतीक है। संकट की इस घड़ी में समस्त मनरेगा कर्मी दिवंगत साथी के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।

तालसा क्लब में यूसीआई के सीएसआर से स्वास्थ्य शिविर

जमशेदपुर : भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी जमशेदपुर द्वारा यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर से 2 जून को आदिवासी नवयुवक क्लब, तालसा में ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। शिविर से तालसा, तुरामडीह, छोटा तालसा, बिंदापुर, धतकीडीह, पाथरडीह गांव के आदिवासी व ग्रामीण लाभान्वित हो सकेंगे। रेड क्रॉस सोसाईटी, पूर्वी सिंहभूम के मानद सचिव विजय कुमार सिंह ने शिविर में अधिक से अधिक ग्रामीणों से भाग लेकर शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

बाइक चोर गिरोह के दो आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर

जमशेदपुर : सिदगोड़ा थाना क्षेत्र से चोरी की तीन बाइक के साथ गिरफ्तार दो आरोपियों रंजीत धीवर और शेखर प्रमाणिके की जमानत अर्जी मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मंजूर हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्या सिंह द्वारा जमानत अर्जी मंजूर होने के साथ ही शेखर प्रमाणिक का बेलबॉन्ड भी अदालत में दिया गया। अधिवक्ता के अनुसार 7 मई को पुलिस ने 4 आरोपियों को बाइक चोरी ल में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

अपराधी रवि खेड़ा ने कोर्ट में किया सरेंडर

जमशेदपुर : गोलमुरी थाना अंतर्गत गाढ़ाबासा में फायरिंग करने के आरोपी कुख्यात अपराधी रवींद्र सिंह उर्फ रवि खेड़ा ने मंगलवार को पुलिस ने दबाओ में आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। रवि ने सिविल जज विश्वनाथ उरांव के कोर्ट में सरेंडर किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रवि पर गोलमुरी समेत अन्य थानों में आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज है। बीते दिनों गोलमुरी में लोचन पर फायरिंग की गई थी। इस मामले में रवि फरार चल रहा था।

3 जून को लोहिया नेत्रालय बागबेड़ा में लगेगा रक्तदान शिविर

जमशेदपुर : बागबेड़ा थाना चौक स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में 3 जून को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। रेड क्रॉस के विजय कुमार सिंह ने अपील की है कि बागबेड़ा एवं आसपास के लाल बिल्डिंग, हरहरगुडु, रानीडीह, गाराबासा, नया बाजार, जुगसलाई के युवाओं से अनुरोध है कि वे शिविर में रक्तदान कर इस आपातकालीन स्थिति से शहर को बाहर निकालने में अपनी क्षमता का उपयोग करें।

रांची इंटरसिटी व बाबाधाम इंटरसिटी में बढ़ेंगी दो एसी चेयरकार

धनबाद : धनबाद से राजधानी रांची के साथ-साथ उप राजधानी दुमका तथा गोड्डा के बीच सफर आसान होने वाला है। बढ़ती गर्मी में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को एसी में सफर का विकल्प दिया जाएगा। रेलवे ने धनबाद होकर चलने वाली गोड्डा की दोनों ट्रेनों में थर्ड एसी बोगी बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही धनबाद से खुल कर रांची जाने वाली इंटरसिटी और धनबाद-दुमका होकर रांची से गोड्डा जाने वाली इंटरसिटी में एसी चेयरकार के साथ-साथ नन एसी बोगी में भी स्थायी रूप से बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस में रांची से छह जून से और 18604 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस में सात जून से एक की जगह चार थर्ड एसी बोगी जोड़ी जाएंगी। साथ ही इस ट्रेन में एक स्लीपर बोगी भी उसी दिन से बढ़ाई जाएगी। भागलपुर होकर गोड्डा जाने वाली इस ट्रेन में अब 17 की जगह 21 बोगियां होंगी।इसी तरह 18619 रांची-गोड्डा इंटरसिटी में पांच जून से रांची से दो की जगह चार एसी थ्री बोगी जोड़ी जाएंगी। वापसी में 18620 गोड्डा-रांची इंटरसिटी में छह जून से नया कंपोजिशन बहाल किया जाएगा। इन देनों ट्रेनों के अलावा धनबाद से खुलने वाली 13303 धनबाद-रांची इंटरसिटी और दुमका से खुलकर धनबाद होते हुए रांची जाने वाली 13319 दुमका-रांची बाबाधाम इंटरसिटी में एक की जगह तीन एसी चेयरकार बोगी जोड़ी जाएंगी। दो एसी चेयरकार बोगी बढ़ाने के साथ-साथ ट्रेन में तीन नन एसी बोगी भी बढ़ाई जाएंगी। इन दोनों ट्रेनों को नई संरचना के साथ चलाने की हरी झंडी दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने दे दी है। जल्द इसकी तिथि की घोषणा की जाएगी। डेली पैसेंजरों की सहूलियत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नियमित यात्रा करने वालों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को भी इस फैसले से काफी फायदा मिलेगा।

भौंरा में गला रेतकर युवक की हत्या, एक हिरासत में

धनबाद : भौंरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत काली मेला बिनोद पुल के निकट दामोदर नदी किनारे स्थित श्मशान घाट के यात्री शेड में सोमवार सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से 22 वर्षीय युवक की हत्या की थी। फर्श और सीढ़ियों पर काफी खून बिखरा था। सूचना मिलते ही भौंरा ओपी प्रभारी सुमन सौरभ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटनास्थल से पुलिस ने एक काले रंग की बाइक, चाभी, पॉलीथिन में रखा खाने-पीने का सामान, नमकीन, प्लास्टिक का ग्लास और चप्पल बरामद किया। दोपहर करीब 1:30 बजे मोबाइल पर वायरल फोटो को देखकर मृतक के चाचा वसीम अंसारी घटनास्थल पहुंचे और शव की पहचान होरलाडीह 3 नंबर निवासी दिलशाद अंसारी के रूप में की।

श्रावणी मेला: एआई तकनीक से होगी श्रद्धालुओं की निगरानी, मंत्री ने की समीक्षा बैठक

संवाददाता

देवघर : बाबा नगरी में आयोजित होने वाला श्रावणी मेला पूरे झारखंड ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। एक महीने तक चलने वाले इस मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

सोमवार को झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर और दुमका जिला के अधिकारियों के साथ श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों, आवश्यक संसाधनों और आवंटन राशि से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने विभागवार जरूरतों और योजनाओं की सूची मंत्री को सौंपी।

इस बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि इस वर्ष श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए जा रहे हैं। विशेष रूप से तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि हर वर्ष मेला के लिए अस्थायी रूप से तैयार किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को स्थायी स्वरूप दिया जाए। जिससे भविष्य में बार-बार टेंडर और निर्माण कार्यों की आवश्यकता कम हो सके।

मंत्री ने बताया कि दुमका प्रशासन की ओर से भी बासुकीनाथ में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में दोनों जिलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी देने के साथ संभावित चुनौतियों और समस्याओं को भी साझा किया। दुमका-बासुकीनाथ मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से बातचीत कर मेला शुरू होने से पहले सड़क को पूरी तरह दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बनाए जाने वाले टेंटों में एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। जिला में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं की संख्या का आकलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा रूट लाइन पर फेस डिटेक्शन कैमरों की मदद से भी श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।

इस समीक्षा बैठक में देवघर के उपायुक्त सौरव कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीन पुष्कर, नगर आयुक्त रोहित सिन्हा, एसडीएम रवि कुमार, विधायक चुन्ना सिंह, विधायक सुरेश पासवान सहित देवघर और दुमका जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मालिन में बंद मिला स्वास्थ्य उपकेंद्र

कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

संवाददाता

साहिबगंज : कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग के जिला अध्यक्ष प्रमित तिवारी ने मालिन ग्राम स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र मालिन का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पाया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई।प्रमित तिवारी ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र नियमित रूप से बंद रहता है और मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं।शिकायतों की सत्यता जांचने के लिए उन्होंने स्वयं स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया,जहां अस्पताल बंद मिला।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार और स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।यदि स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका रहेगा तो आम लोगों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा,जो बेहद गंभीर विषय है।प्रमित तिवारी ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।स्थानीय ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र को नियमित रूप से संचालित करने व चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।जिला अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाकर समाधान का प्रयास किया जाएगा।साथ में विक्की यादव, गोपाल साहा, संतोष मिश्रा, अमरकांत भगत,अरुण साहा आदि मौजूद थे।

आईना वही रहता है चेहरे बदल जाते हैं

समय समय की बात वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई

बिनय मिश्रा

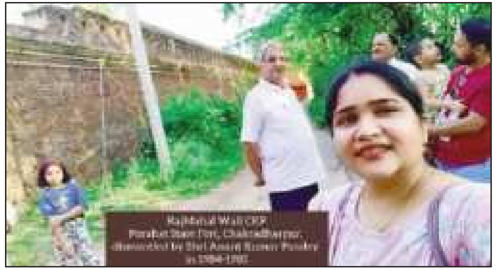

चक्रधरपुर का ऐतिहासिक किला राजवाड़ी को महाविद्यालय बनाने के लिए जो संवेदक थे वो सपरिवार बयालीस वर्षों बाद इसका अवलोकन करने चक्रधरपुर पहुंचे और काफी आत्म विभोर भी हुए । चक्रधरपुर का ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ी किला जो पूरे क्षेत्र का शान था इसके ध्वस्त होने की स्थिति में इसे तत्कालीन हजारीबाग के राज परिवार ने इसे चक्रधरपुर के सी जे पटेल को दे दिया बाद में सी जे पटेल के द्वारा इसे जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य जो रांची के तत्कालीन विधायक ननी गोपाल मित्रा को महाविद्यालय के लिए दे दिया। ध्वस्त होने के कगार पर इस राजमहल को तोड़ने और सुरक्षित रखने के लिए जमशेदपुर के संवेदक बैद्यनाथ पांडेय और उनके पुत्र अनंत कुमार पांडेय को इसकी जवाबदेही दी गई जिसकी जवाबदेही अनंत कुमार पांडेय के देखरेख में कुशलता पूर्वक किया गया और वर्तमान समय में जवाहरलाल महाविद्यालय इस राजमहल में स्थापित है। बयालीस वर्षों के पश्चात अनंत पांडेय सपरिवार इस स्थल और महाविद्यालय को देखने जमशेदपुर से चक्रधरपुर पहुंचे और काफी भावविभोर हुए। श्री पांडेय की पुत्री आभा रश्मि यहां पहुंच कर काफी हर्षित हुई और कहा कि उनके पूज्य दादा जी और पिता अनंत पांडेय के अथक परिश्रम और प्रयास से राजवाड़ी किला अब शिक्षा का मंदिर बन चुका है जिसमें ज्ञान प्राप्त कर कई छात्र महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं।वह अपने पिता के उपलब्धि पर काफी हर्षित और गौरवान्वित भी है और कहती है - इनके प्रयास से हो पाया है शिक्षा के क्षेत्र का मंदिर का निर्माण

दूसरे विभाग वाले गोदाम प्रबंधकों की होगी छुट्टी, बीएसओ को प्रभार

जमशेदपुरः आपूर्ति विभाग अब दूसरे विभाग के सहायक गोदाम प्रबंधकों (एजीएम) को नहीं रखेगा। उनकी जगह प्रखंडों में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (बीएसओ) को यह दायित्व संभालना होगा। इस आशय का आदेश खाद्य आपूर्ति विभाग से ही सोमवार को जारी हो गया। विभाग ने माना है कि दूसरे विभाग के कर्मचारियों को यह प्रभार दिये जाने की वजह से वे अपने मूल विभाग के काम में अधिक रुचि लेते रहते हैं, जिसके कारण गोदाम प्रबंधन ठीक से नहीं होता। विभाग ने आदेश दिया है कि स्टॉक का मिलान कर एक सप्ताह में सभी संबंधित बीएसओ प्रभार संभाल लें। हाल के समय में पूर्वी सिंहभूम जिले में एजीएम की मनमानी की वजह से डोर स्टेप डिलिवरी में देर और लाभुकों को राशन समय पर नहीं मिलने की शिकायतें बढ़ गई हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में जनसेवक और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को यह दायित्व मिला हुआ है।

रोटरी क्लब चाईबासा में 168 वां रक्तदान शिविर हुआ संपन्न

संवाददाता

चाईबासा : रोटरी क्लब चाईबासा द्वारा स्व हरभजन सिंह खोखर की स्मृति में 1 जुलाई 2012 को आरंभ किए गए रोटरी मासिक रक्तदान सह जागरुकता का आज लगातार 168 वां शिविर आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

प्रत्येक माह की पहली तिथि को नियमित रूप से आयोजित होने वाली रोटरी मासिक रक्तदान शिविर ने लगातार 14 वर्ष की शानदार उपलब्धि आज 1 जून को हासिल कर ली। इस कार्यक्रम के स्थायी संयोजक रोटेरीयन गुरमुख सिंह खोखर ने कहा कि इसका श्रेय निस्वार्थी स्वैच्छिक रक्तदाताओं को जाता है साथ ही ब्लड बैंक कर्मियों का भी सहयोग मिलता है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष विकास दोदराजका ने अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि रक्त दान करने से शरीर को नवीन ऊर्जा मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं दान किए रक्त से किसी का जीवन बचता है यह एक महान कृत्य है हमें इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने इलेक्ट्रोनिक एंड प्रिंट के साथियों को भी सराहनीय सहयोग और उनकी प्रशंसनीय भूमिका के लिए के लिये आभार व्यक्त किया उन्होंने स्पष्ट किया की समाचार प्रणाली से लोगों विशेषकर युवाओ को रक्तदान के प्रति झिझक दूर हुई है, उनका निरंतर सहयोग मिलता रहा है।

ajan Singh Khokhar
Y BLOOD DONATION CAMP
JUNE 2026, Monday
ospital (MTC BUILDING) Chaiba a
KHOKHAR FAMILY, CHAIBASA

आज के शिविर में कुल 12 (बारह) रक्तदाताओं ने रक्तदान किया ' आज सर्वप्रथम रक्तदान करने वाले अभिजीत रक्षित सहित कुल बारह रक्तदाताओं को पुष्प गुच्छ एवं प्रस्सति पत्र देकर सम्मानित किया गया मौके पर रोटरी अध्यक्ष विकास दोदराजका, मदन गुप्ता, महेश खत्री, अमन प्रसाद गुप्ता, रोट्रेक्टर निशांत, अक्षय गुप्ता एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे।

धनबाद में युवक को गोली मारकर आपराधियों ने लूट ली बाइक

धनबादः जिले में सोमवार की सुबह तोपचांची थाना क्षेत्र में बाइक से जा रहे एक युवक को गोली मार दी गई। घटना के बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। घायल युवक को इलाज के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हालांकि, पुलिस की शुरूआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और इसके तार कोयला खनन क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

घायल युवक की पहचान बोकारो जिले के दुग्दा थाना क्षेत्र के अटारी गांव निवासी रवि बख्श राय के रूप में हुई है। रवि ने पुलिस को बताया कि वह अपने एक मित्र के साथ बाइक से देवघर जा रहा था। इसी दौरान तोपचांची बाजार के समीप दो बाइक पर सवार अपराधियों ने उसे रोकने का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दो गोलियां उसके पैरों में लगीं। इसके बाद हमलावर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल, तोपचांची थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को घायल और उसके साथ मौजूद लोगों के बयान में कई विरोधाभास मिले। इसके बाद पुलिस को संदेह हुआ कि घटना की वास्तविक कहानी कुछ और हो सकती है।

एसडीपीओ अजीत कुमार बिमल ने बताया कि घटनास्थल की जांच में न तो खून के निशान मिले और न ही गोली चलने से संबंधित कोई साक्ष्य बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह संभावना सामने आई है कि फायरिंग की घटना दुग्दा क्षेत्र में कोयला खनन से जुड़े वर्चस्व विवाद के दौरान हुई हो और बाद में घायल को इलाज के लिए धनबाद लाकर घटना को तोपचांची क्षेत्र का बताया गया हो। फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जल्द ही संभावित वास्तविक घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : विकास दोदराजका

बिनय मिश्रा

चाईबासा : बाल कल्याण संघ द्वारा संचालित बालगृह बालकुंज में बच्चों के संरक्षण, देखभाल एवं उनके सर्वांगीण विकास को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रेन डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष चर्चा हुई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल संरक्षण कार्यकर्ता विकास दोदराजका ने कहा कि बच्चों को सुरक्षा, स्नेह एवं उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, बच्चों को परिवार एवं समाज से जोड़कर ही उनके उज्ज्वल एवं आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों में असीम संभावनाएं छुपी होती है जिन्हें उचित अवसर एवं मार्गदर्शन देकर निखारने की आवश्यकता है।

साथ ही उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज एवं परिवारों को बाल संरक्षण के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण माध्यम है,

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी ने कहा कि बच्चों को संस्थागत देखभाल के साथ-साथ पारिवारिक माहौल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारा जिला पूरे राज्य में सर्वाधिक बच्चों को फोस्टर केयर से जोड़ने वाला पहला जिला बनकर उभरा है, जो बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल है।

उन्होंने कहा कि बच्चों के भावनात्मक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में पारिवारिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कार्यक्रम में संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि संस्था का उद्देश्य बच्चों को केवल आश्रय उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें पारिवारिक वातावरण, शिक्षा, संस्कार एवं आत्मविश्वास प्रदान कर बेहतर जीवन के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को प्रेम, सम्मान एवं अपनापन मिलना चाहिए, ताकि वे समाज में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि संस्था का लक्ष्य बालगृह को राज्य में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है, जहां से निकलने वाले बच्चे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ सकें।